twitter.com/divyadelhi facebook.com/divyadelhi infodivyadelhi@gmail.com Editor: Rajesh Chauhan

RNI No. DLHIN/25/A2321

दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

दिव्य दिल्ली

divyadelhi.com | शुक्रवार, 29 अगस्त, 2025 | वर्ष: 01, अंक: 01, पृष्ठ: 08 | ₹ 05/- 09/- दिव्य दिल्ली (इंग्लिस पेपर सहित)

राज्य सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन नहीं दे सकते: केंद्र

राष्ट्रपति-राज्यपाल अपने फैसलों के लिए कोर्ट में जवाबदेह नहीं; डेडलाइन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राज्य सरकारें उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका (मामला) नहीं कर सकतीं जो राष्ट्रपति या राज्यपाल ने विधानसभा से पास हुए विधेयकों पर लिया हो, चाहे राज्य यह कहे कि इससे लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

सरकार ने क्या कहा

केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह बात चीफ जस्टिस (सीजेआई) बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ के सामने कही। संविधान पीठ में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर भी शामिल थे। मेहता ने कहा कि राष्ट्रपति इस बात पर सुप्रीम कोर्ट की राय लेना चाहती हैं कि क्या राज्य सरकारें संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ऐसी याचिकाएं दायर कर सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति यह भी जानना चाहती हैं कि संविधान के अनुच्छेद 361 का दायरा क्या है। यह अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने अधिकारों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। मेहता ने संविधान पीठ को बताया कि इन सवालों पर पहले भी चर्चा हुई है। लेकिन राष्ट्रपति का मत है कि अदालत की स्पष्ट राय जरूरी है, क्योंकि भविष्य में ऐसा मामला फिर उठ सकता है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत राज्य सरकार की ओर से राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती। न तो कोर्ट ऐसे मामलों में कोई निर्देश दे सकता है और न ही इन फैसलों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने आगे कहा, अनुच्छेद 32 का उपयोग तब किया जाता है, जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। लेकिन सांविधानिक ढांचे में राज्य सरकार खुद मौलिक अधिकार नहीं रखती। राज्य सरकार की भूमिका यह है कि वह अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे।

राज्यपाल का छह महीने तक विधेयक लंबित रखना सही नहीं: सीजेआई

सॉलिसिटर जनरल ने आठ अप्रैल के उस फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर राज्यपाल समयसीमा के भीतर विधेयकों पर फैसला नहीं करते तो राज्य सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं।

इस पर सीजेआई गवई ने कहा कि वह आठ अप्रैल के दो जजों के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन यह भी कहा कि राज्यपाल का किसी विधेयक को छह महीने तक लंबित रखना सही नहीं है। मेहता ने जवाब में कहा कि अगर एक सांविधानिक संस्था अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती, तो इसका मतलब यह नहीं कि कोर्ट दूसरी सांविधानिक संस्था को आदेश दे। इस पर सीजेआई ने कहा, हां, हम समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं। लेकिन अगर यह अदालत ही किसी मामले को 10 साल तक नहीं सुलझाए, तो क्या राष्ट्रपति को कोई आदेश देने का हक होगा? सुनवाई अभी जारी है। 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया था कि अगर कोई राज्यपाल किसी विधेयक पर अनिश्चितकाल तक फैसला नहीं लेता तो क्या अदालत के पास कोई उपाय नहीं रहेगा? क्या राज्यपाल की स्वतंत्र शक्ति के चलते बजट जैसे जरूरी विधेयक भी अटक सकते हैं? शीर्ष कोर्ट ने यह सवाल तब उठाया जब कुछ भाजपा शासित राज्यों ने कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को विधेयकों पर फैसला लेने में पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए।

राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी

सुप्रीम कोर्ट अभी राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए उस सांविधानिक संदर्भ पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें पूछा गया है कि क्या अदालत राज्यपाल और राष्ट्रपति को यह निर्देश दे सकती है कि वे विधानसभा से पारित हुए विधेयकों पर तय समयसीमा में निर्णय लें? मई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी कि क्या अदालत राष्ट्रपति को निर्देश दे सकती है कि वह राज्य विधानसभा से आए विधेयकों पर कब और कैसे फैसला लें। मेहता ने संविधान पीठ को बताया कि इन सवालों पर पहले भी चर्चा हुई है। लेकिन राष्ट्रपति का मत है कि अदालत की स्पष्ट राय जरूरी है, क्योंकि भविष्य में ऐसा मामला फिर उठ सकता है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत राज्य सरकार की ओर से राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती।

न तो कोर्ट ऐसे मामलों में कोई निर्देश दे सकता है और न ही इन फैसलों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने आगे कहा, अनुच्छेद 32 का उपयोग तब किया जाता है, जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।

लेकिन सांविधानिक ढांचे में राज्य सरकार खुद मौलिक अधिकार नहीं रखती। राज्य सरकार की भूमिका यह है कि वह अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे।

रेल बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा

नई दिल्ली

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका कार्यकाल 31 अगस्त, 2025 को समाप्त होना था। सरकार के 27 अगस्त के आदेश में कहा गया है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा सेवानिवृत्त सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में एक सितंबर, 2025 से एक और वर्ष के लिए अनुबंध आधारित दोबारा नियुक्ति को मंजूरी दी है। यह मौजूदा नियम और शर्तों पर या आगे के आदेश तक होगा, जो भी पहले हो। सतीश कुमार की एक सितंबर, 2024 को हुई प्रारंभिक नियुक्ति ने उन्हें बोर्ड के इतिहास में अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले पहले अध्यक्ष और सीईओ बनाया। अधिकारी बताते हैं कि 1986 बैच के भारतीय रेलवे यांत्रिक इंजीनियर सेवा (आईआरएसएमई) के विशिष्ट अधिकारी कुमार ने अपने 34 वर्षों के शानदार करियर में भारतीय रेलवे के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने मार्च 1988 में भारतीय रेलवे में अपना करियर शुरू किया।

देश के हर हिस्से में पहुंची पीएनजी

नई दिल्ली

द्वीपीय इलाकों को छोड़ दें तो देश के 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लगभग 784 जिलों में (100 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र) में पाइप्ड नेचुरल गैस (एनजी) पहुंच गई है।

पीएनजी कनेक्शनों की संख्या 12 करोड़ करने लक्ष्य

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने कहा है कि उसने 2034 तक 12.63 करोड़ पीएनजी घरेलू कनेक्शन, 18,336 सीएनजी स्टेशन और 5.46 लाख किलोमीटर पाइप्ड गैस कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया है। बोर्ड ने कहा, ''लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, राज्यों और संस्थाओं के बीच एक मजबूत और समन्वित तालमेल अनिवार्य है।'

कई नीतिगत और नियामक उपाय किए

बोर्ड ने कहा कि सरकार ने इस क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए कई नीतिगत और नियामक उपाय किए हैं।

एससीओ: मोदी-जिनपिंग की होगी मुलाकात

नई दिल्ली

ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच मीटिंग की डेट फाइनल हो गई है। दोनों नेता रविवार को तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय बैठक करेंगे।

जापान की अपनी दो दिवसीय यात्रा के समापन के बाद पीएम मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति शी के निमंत्रण पर चीन में होंगे। माना जा रहा है कि इस द्विपक्षीय वार्ता में ट्रंप टैरिफ पर भी बात होने की संभावना है। 31 अगस्त को दोनों की मुलाकात

एससीओ समिट से इतर दोनों नेताओं की मुलाकात 31 अगस्त को होगी। यह पिछले सात वर्षों में पीएम मोदी की पहली चीन यात्रा होगी और जून 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुए टकराव के बाद पहली यात्रा होगी। दोनों नेताओं ने 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर एक बैठक की थी। भारत और चीन के बीच चार साल से चल रहे सीमा टकराव को समाप्त करने के लिए लगभग 3500 किलोमीटर लंबी एलएसी पर गश्त करने के समझौते के बाद द्विपक्षीय वार्ता में सफलता संभव हुई। 21 अगस्त को भारत में चीन के राजदूत जू फीहोंग ने कहा कि एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी की तियानजिन यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों के सुधार और विकास को एक नई गति प्रदान करेगी।

भारी बारिश और लैंडस्लाइड से जम्मू-हिमाचल को तगड़ा नुकसान, फलों-सब्जियों के हजारों ट्रक फंसे

नई दिल्ली

इस बार का मानसून कहर बनकर बरस रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। यातायात ठप पड़े हैं। मौसम विभाग का भी कहना है कि उत्तर भारत और पहाड़ों में अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। जम्मू के वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड होने से 35 लोगों की मौत भी हो गई है। दिल्ली-एनसीआर, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में तबाही मचाने के बाद भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। पहाड़ी इलाकों में लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है। इसके कारण जम्मू जैसे इलाके में भूस्खलन और रास्ते बंद होने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि, बारिश के कारण थोड़ा तापमान भी कम होने की संभावना है।

चंडीगढ़-कुल्लू हाईवे पर महाजाम

भूस्खलन की सबसे ज्यादा मार कुल्लू झेल रहा है। यहां चंडीगढ़-कुल्लू हाईवे पर लैंडस्लाइड होने से हजारों ट्रक फंस गए हैं, जिसके चलते सेब, टमाटर और अन?य सब्जियां पूरी खराब होती जा रही है। यहां छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता तो खोला गया है, लेकिन हजारों ट्रक अभी भी फंसे हुए हैं।

हिमाचल प्रदेश में 534 सड़कें बंद, 310 की मौत

हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण 534 सड़कों को बंद करना पड़ा है। जबकि 1,184 बिजली वितरण ट्रांसफार्मर बाधित हुए हैं। एसडीएमए ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन, अचानक आई बाढ़ और मकान ढहने से राज्य भर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 310 हो गई है। कुल्लू में सबसे ज्यादा सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं, जहां एक राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 166 सड़कें बंद हैं।

राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी की मां को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग करना निंदनीय: प्रधान

नई दिल्ली

बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर नई सियासी बहस छिड़ गई है। भाजपा और एनडीए के कई नेताओं जैसे धर्मेंद्र प्रधान और चिराग पासवान ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग करना निंदनीय और शर्मनाक है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि ये भाषा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित पूरे इंडी गठबंधन की प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नफरत की पराकाष्ठा को दिखाता है। राजद-कांग्रेस के चुनावी मंच से आई ये घृणित टिप्पणी बिहार सहित पूरे देश के हर उस भारतीय का अपमान है, जो अपनी मां को ईश्वरतुल्य मानते हैं।

उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि बिहार को अपमानित करने वालों को बढ़ावा देने के बाद अपने निजी आक्रोश और नफरत में प्रधानमंत्री की दिवंगत माताजी के खिलाफ ऐसी भाषा, इन नेताओं और दलों की खोखली मानसिकता और चरम निराशा का प्रमाण है। लगातार जनता से आशीर्वाद और समर्थन न मिल पाने की हताशा अब इन नेताओं की भाषा और आचरण से साफ झलक रही है। बिहार की जनता सब देख रही है। पहले बिहार को अपमानित करने और अब प्रधानमंत्री की माताजी को लेकर इस असंवेदनशील व अमर्यादित व्यवहार का जवाब जनता अपने वोट की चोट से देगी।

जल, थल, नभ के साथ अब साइबर और स्पेस में एक साथ होगा दुश्मन पर प्रहार

इंदौर

भारतीय सेना के जल, थल और नभ के कम्युनिकेशन एवं रडार सिस्टम अब एक साथ मिलकर दुश्मन का सामना करेंगे। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ने इस दिशा में एक संयुक्त सैन्य सिद्धांत (डाक्ट्रिन) तैयार किया है, जो साइबर, स्पेस, इलेक्ट्रानिक वारफेयर और ड्रोन के माध्यम से दुश्मन को चुनौती देने के लिए है।

महू में आयोजित रण संवाद में रक्षा मंत्री ने किया संबोधित

महू वॉर कॉलेज में आयोजित दो दिवसीय रण संवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इस डाक्ट्रिन को जारी किया। इस डाक्ट्रिन के तहत विशेष बलों और एयर बोर्न व हेली बोर्न संचालन के लिए भी संयुक्त सिद्धांत जारी किए गए हैं। इसके अनुसार, एयर बोर्न और हेली बोर्न यूनिट अब मल्टी मॉडल डोमेन पर संयुक्त रूप से कार्य करेंगी। सेना के अधिकारियों के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मल्टी डोमेन ऑपरेशन की आवश्यकता को देखते हुए यह डाक्ट्रिन तैयार की गई है। इसका मुख्य लाभ यह होगा कि सेना तीनों इकाइयों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर किसी भी आपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकेगी। इस आधार पर सेना पहली बार हाइब्रिड मॉडल अपनाकर दुश्मन को चारों ओर से नुकसान पहुंचाने के साथ देश की सुरक्षा करेगी।

भारत कभी भी युद्ध की इच्छा रखने वाला देश नहीं रहा है, लेकिन यदि कोई चुनौती प्रस्तुत करता है तो भारत उसे पूरी ताकत से जवाब देने के लिए तैयार है।

अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके से सहमे लोग

ईटानगर

अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में सुबह-सुबह भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) ने बताया कि भूकंप सुबह 8.05 बजे आया और इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में एनसीएस ने बताय कि भूकंप की तीव्रता 3.6 मैग्निट्यूड आंकी गई है। भूकंप के बाद किसी जानमाल की हानी की बात सामने नहीं आई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, इससे पहले 23 अगस्त को असम के कार्बी आंगलोंग में 2.7 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था। वहीं, इससे पहले 21 अगस्त को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में 3.5 तीव्रता का भूकंप आया था।

बड़े औद्योगिक और श्रम सुधारों की ओर बढ़ रहा उत्तर प्रदेश, आसान होगा व्यापार: सीएम

लखनऊ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र के अनुरूप आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में औद्योगिक व श्रम सुधारों की दिशा में बड़े कदम बढ़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में उद्योग और व्यापार से जुड़े 13 राज्य अधिनियमों में लगभग 99 प्रतिशत आपराधिक प्रावधान समाप्त करने की तैयारी हो रही है। शीघ्र ही उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जो व्यावहारिकता के दृष्टिकोण से इतने बड़े पैमाने पर आपराधिक प्रावधानों को गैर-आपराधिक श्रेणी में परिवर्तित करेगा। गुरुवार को आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और सशक्त बनाने के लिए नए कदम उठाना समय की मांग है। साथ ही यह भी उतना ही आवश्यक है कि औद्योगिक विकास के साथ श्रमिकों की सुरक्षा और सुविधा की गारंटी सुनिश्चित हो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के श्रमेव जयते के भाव को आत्मसात करते हुए हमें ऐसे सुधार करने होंगे, जो उद्यमियों और श्रमिकों; दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध हों। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार शीघ्र ही सुगम्य व्यापार (प्राविधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 लाने जा रही है। इसके अंतर्गत आबकारी अधिनियम, शीरा अधिनियम, वृक्ष संरक्षण अधिनियम, राजस्व संहिता, गन्ना अधिनियम, भूगर्भ जल अधिनियम, नगर निगम अधिनियम, प्लास्टिक कचरा अधिनियम, सिनेमा अधिनियम तथा क्षेत्र व जिला पंचायत अधिनियम सहित कई कानूनों को अधिक व्यावहारिक स्वरूप दिया जाएगा। इनमें जहाँ पहले कारावास की सजा का प्रावधान था, वहां अब अधिक आर्थिक दंड व प्रशासनिक कार्रवाई को वरीयता देने की योजना है। नए प्रावधानों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अनावश्यक दंडात्मक प्रावधानों को समाप्त कर, उनकी जगह पारदर्शी और न्यायसंगत व्यवस्था लागू करना समय की मांग है। बैठक में अवगत कराया गया कि इस विधेयक पर संबंधित 14 विभागों से राय ली गई है। अधिकांश विभाग सहमत हैं, जबकि कुछ ने आपत्तियाँ दर्ज कराई हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आपत्तियों और सुझावों पर गंभीरता से विचार करते हुए विधेयक को ऐसा स्वरूप दिया जाए, जो उद्योग और श्रमिकों के हितों में संतुलित हो।

बैठक में श्रम कानूनों के सरलीकरण पर भी चर्चा हुई। प्रस्तावों में फैक्ट्री लाइसेंस की अवधि बढ़ाने, दुकानों व प्रतिष्ठानों के नियमों में व्यावहारिक बदलाव करने और महिलाओं को अधिक अवसर उपलब्ध कराने जैसे कदम शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि निरीक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए स्व-सत्यापन और थर्ड पार्टी ऑडिट की प्रणाली अपनाई जानी चाहिए।

पीडब्ल्यूडी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के 20 वर्षों के मध्यस्थता निर्णयों की होगी समीक्षा : रेखा गुप्ता

एजेंसी

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (पीडब्ल्यूडी/आईएंडएफसी) की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है, जो लोक निर्माण विभाग और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग में पिछले 20 वर्षों में एक करोड़ रुपये एवं उससे अधिक के मध्यस्थता निर्णयों (आर्बिटेशन अवॉर्ड) की समीक्षा करेगी। मुख्यमंत्री के अनुसार इस समिति के गठन का उद्देश्य सरकार के विरुद्ध दिए गए निर्णयों की जानकारी, भुगतान की राशि और नुकसान आदि का आकलन करना है।

मुख्यमंत्री ने एक विज्ञप्ति में जानकारी दी कि इस उच्चस्तरीय समिति में लेखा परीक्षा नियंत्रक को सदस्य एवं अतिरिक्त महानिदेशक (पीडब्ल्यूडी/आईएंडएफसी) को सदस्य सचिव बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पीडब्ल्यूडी एवं बाढ़ व सिंचाई नियंत्रण विभाग की आंतरिक वित्त संबंधी सहायक टीम क्रमशः (सीओए) एवं (डीसीए) के अलावा लेखा परीक्षा निदेशालय की दो लेखा परीक्षा टीमें समिति की सहायता करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह समिति दोनों विभागों में पिछले 20 वर्षों में 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के मध्यस्थता निर्णयों की समीक्षा करेगी। यह समिति ऐसे निर्णयों की वर्षवार एवं निर्णयवार आंकड़े उपलब्ध कराएगी।

इनमें मध्यस्थता मामलों की कुल संख्या भी शामिल है। समिति यह भी विवरण देगी कि इन वर्षों में सरकार के खिलाफ कितने निर्णय दिए गए। इनमें भुगतान की राशि की तो जानकारी शामिल होगी ही साथ ही समिति यह भी विवरण देगी कि इन निर्णयों में सरकार को कितना नुकसान उठाना पड़ा। दोनों विभागों द्वारा संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराए जाने के बाद समिति इनकी समीक्षा (ऑडिट) की प्रक्रिया शुरू कर देगी। यदि आवश्यकता हुई तो समिति की सिफारिश पर लेखा परीक्षा निदेशालय कार्य की मात्रा या अधिकता के आधार पर अतिरिक्त लेखा परीक्षा टीमें उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस समीक्षा का उद्देश्य कानूनी विवादों से होने वाले वित्तीय नुकसान की सीमा का आकलन करना और पिछले दो दशकों में सार्वजनिक धन के खर्च या नुकसान के बारे में पारदर्शिता लाना है। मुख्यमंत्री के अनुसार ऐसा देखा जा रहा है कि मध्यस्थता निर्णयों से सरकार को लगातार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि अभी हाल ही में उन्होंने बारापुला फेज-द्वद्वद्व कॉरिडोर के निर्माण में अनियमितताओं और देरी के कारण उत्पन्न मध्यस्थता मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक शाखा से कराने का आदेश दिया था। अक्टूबर 2017 में पूरी होने वाली इस परियोजना में बार-बार देरी हुई और अंततः मध्यस्थता का मामला सामने आया। यह फैसला ठेकेदार के पक्ष में आया और उसे 120 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया।

खाई में पलटी स्कूल बस, 12 से ज्यादा बच्चे घायल, चालक पर लापरवाही का आरोप

एजेंसी

हल्द्वानी । उत्तराखंड के हल्द्वानी के लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के बरेली रोड पर जयपुर बीसा गांव में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। निजी स्कूल की एक बस, जिसमें बच्चे सवार थे, दूसरी बस को साइड देने के चक्कर में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बस का शीशा तोड़कर सभी बच्चों को बाहर निकाला, जिसमें 12 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बस

चालक और परिचालक को भी गंभीर चोटें आई हैं। हादसा मोटाहल्दू क्षेत्र के पदमपुर देवलिया गांव के पास हुआ, जहां बस रामपुर रोड से बच्चों को स्कूल ले जा रही थी। घटनास्थल स्कूल के नजदीक होने की वजह से स्थानीय लोगों ने निजी वाहनों से घायलों को हल्द्वानी के निजी अस्पताल पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दो स्कूल बसें चौराहे के पास साइड ले रही थीं। इस दौरान एक बस ज्यादा किनारे चली गई और खाई में पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही क्षेत्र के अभिभावक चिंता में पड़ गए और स्कूल पहुंचकर अपने बच्चों की कुशलक्षेम पूछने लगे। ग्राम प्रधान रमेश चंद्र जोशी ने हादसे के लिए बस चालकों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कि बस में करीब 40 बच्चे सवार थे, जिनमें से 12 से ज्यादा घायल हुए। प्रधान ने कहा, इस क्षेत्र के बस चालक अक्सर नशे की हालत में गाड़ी चलाते हैं। पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने बताया कि हादसे वाली जगह पर नाला है, लेकिन शुक्र है कि नाले में पानी नहीं था, वरना कई बच्चों की जान जा सकती थी। वहीं, ग्राम प्रधान ने जिला प्रशासन पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा। स्थानीय लोगों ने ही घायलों को बचाकर अस्पताल भेजा। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और लोगों ने स्कूलों में सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने की मांग उठाई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

गाजा में पत्रकारों की हत्या स्तब्धकारी और अत्यंत खेदजनक : भारत

नई दिल्ली।भारत ने इजरायल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान गाजा पट्टी पर हमले में पत्रकारों की मौत की निंदा करते हुए इसे

अफसोस जनक करार दिया है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गाजा पट्टी के खान यूनिस में हमलों में पत्रकारों की मौत के संबंध में मीडिया के प्रश्नों के जवाब में बुधवार को कहा कि भारत ने संघर्षों के दौरान आम नागरिकों के मारे जाने की हमेशा निंदा की है। उन्होंने कहा , पत्रकारों की हत्या स्तब्धकारी और अत्यंत खेदजनक है। भारत ने हमेशा संघर्ष में नागरिकों की जान जाने की निंदा की है। हम समझते हैं कि इज़रायली अधिकारियों ने पहले ही जाँच शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि सोमवार को गाजा पट्टी पर इजरायली हमले में पांच पत्रकारों की मौत हुई है। इसे लेकर इजरायली सेनाओं की दुनिया भर में आलोचना हो रही है।

श्रीनगर में बाढ़ जैसी स्थिति

▸▸ बिजली-पानी, आवागमन और इंटरनेट पर आफत

एजेंसी

जम्मू-कश्मीर। जम्मू-कश्मीर में मौसम का कहर जारी रहा है। श्री माता वैष्णो देवी के यात्रा मार्ग पर अर्द्धकुंवारी में स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास हुए भूस्खलन से मरने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 34 पहुंच गई। इनमें 11 उत्तर प्रदेश के हैं। मंगलवार देर रात तक नौ श्रद्धालुओं की मौत और 21 के घायल होने की पुष्टि हुई थी। बाद में बचाव दल को मलबे के नीचे से कई और शव मिले। तलाशी अभियान अभी भी जारी है। आशंका है कि मलबे में अभी भी कई लोग फंसे हो सकते हैं। हादसा मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे पहाड़ का हिस्सा ढहने से हुआ। इससे चट्टानें और मलबा नीचे गिरा और लोग दब गए। जम्मू में चौबीस घंटे में 380 मिमी बारिश दर्ज हुई जोकि पिछले 115 वर्षों में सबसे ज्यादा बारिश है। जम्मू संभाग में नदियों का जलस्तर घटा तो

कश्मीर संभाग में बढ़ गया। भारी बारिश के कारण बिजली-पानी, आवागमन और इंटरनेट सब पर आफत रही। जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश ने कहर मचाया हुआ है, बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन की घटना हुई हैं। जम्मू में कटरा से हैं। लगातार भारी बारिश की वजह से बाढ़ और जलजमाव के चलते अब तक तीन हजार से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर वैष्णो देवी यात्रा दूसरे दिन भी बंद रखी गई। लेकर डोडा तक भारी नुकसान हुआ है। कई पुल टूटे हैं, बिजली की लाइन और मोबाइल टावर भी क्षतिग्रस्त हुए आज भी यात्रा को बहाल नहीं किया गया है। जम्मू संभाग में नदी नालों में जल स्तर घटने से राहत रही, लेकिन कश्मीर में कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति रही। कई कस्बे और गांव डूब गए हैं। श्रीनगर और अनंतनाग में झेलम उफान पर रही। कई इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकाला गया।

चक्की पुल पठानकोट में जमीन धंसने के कारण जम्मू से आने और जाने वाली 58 ट्रेनों को रद्द किया गया और 46 ट्रेनों निर्धारित गंतव्य से पहले ही रोक दिया गया। 18 ट्रेनों को मूल के बजाय अन्य स्टेशनों से चलाया गया। कश्मीर घाटी में रात भर भारी बारिश होने से मुख्य झेलम नदी में बुधवार सुबह अनंतनाग जिले के संगम और श्रीनगर के राम मुंशी बाग में बाढ़ की चेतावनी के निशान को पार कर गई।

छत्तीसगढ़ के रायपुर की पहली महिला विधायक रजनी ताई उपासने का निधन

एजेंसी

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की पहली महिला विधायक रजनी ताई उपासने का आज 93 साल की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रही थीं। उनके निधन से पूरे छत्तीसगढ़ में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर की पहली महिला विधायक एवं प्रख्यात पत्रकार जगदीश उपासने तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता व लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने की माताजी रजनी ताई उपासने जी के निधन पर दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि यह समाचार अत्यंत दुःखद है। जनसेवा और समाज हित के प्रति उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। इस दुःख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवारजनों के साथ हैं।ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। रजनी ताई उपासने ने 1977 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज कर इतिहास रचा था। उस समय उन्होंने कांग्रेस की शारदा चरण तिवारी को मात देकर रायपुर सीट अपने नाम की थी। इस जीत के साथ ही वे रायपुर शहर की पहली महिला विधायक बनीं। राजनीति में आने से पहले से ही वे जनसंघ से जुड़ी सक्रिय कार्यकर्ता रहीं और कई आंदोलनों में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी।

पंजाब में बाढ़ : उज्ज, रावी-ब्यास और सतलुज उफनाई, गांव डूबने से हजारों लोग बेघर

एजेंसी

चंडीगढ़। पंजाब के आठ जिले भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। रावी दरिया में उफान के कारण पठानकोट के माधोपुर हेडवर्क्स के चार गेट टूट गए जिससे वहां तैनात 50 कर्मचारी फंस गए। उन्हें हेलीकॉप्टर से निकाल लिया गया। वहीं, गुरदासपुर जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय दबुड़ी में रात से फंसे 381 विद्यार्थियों और 70 शिक्षकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। उधर, पाकिस्तान में रावी दरिया में बाढ़ के कारण श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा व करतारपुर कॉरिडोर में पानी भर गया है। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज ने बताया कि पाकिस्तान से मिली जानकारी के अनुसार श्री करतारपुर साहिब के मुख्य दरबार सहित पूरे परिसर में कई फीट पानी घुस गया है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान आज फिरोजपुर बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा करेंगे। मान सीमावर्ती गांव बारेके में बने राहत कैंप में लोगों से मिलेंगे और पत्रकारों से बातचीत करेंगे। वे दोपहर 12 बजे तक पहुंचेंगे। फिरोजपुर में सरहिंद नहर पर बना पुल टूट गया जिससे कई गांवों का संपर्क कट गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पठानकोट और गुरदासपुर के

बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। सीएम ने अपना हेलिकॉप्टर वहीं छोड़ दिया ताकि इसे लोगों को बचाने में इस्तेमाल किया जा सके। पंजाब में रावी, ब्यास और सतलुज नदियों में जलस्तर बढ़ने से पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर और फाजिल्का जिलों के 200 से अधिक गांव डूब गए हैं। यहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना बचाव कार्य में जुटी है। माधोपुर हेडवर्क्स के गेट टूटने से सिंचाई विभाग के कर्मचारी विनोद कुमार पानी के तेज बहाव में बह गए जिनकी तलाश की जा रही है। पठानकोट के शाहपुरकंडी की तरफ रणजीत सागर बांध से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सुजानपुर में बाढ़ ने कई घरों व जेएंडके-पठानकोट नेशनल हाईवे को चपेट में ले लिया है। रावी के ऊपर बने रेलवे पुल का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। कठुआ-पठानकोट पुल पर भी आवाजाही बंद कर दी गई है। सुजानपुर के अतेपुर क्षेत्र में जगतार नाम का व्यक्ति पानी के तेज बहाव में बह गया। पठानकोट के डीसी आदित्य उप्पल, एसपी दलजिंदर सिंह ने बताया कि सेना और एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं। सुजानपुर में गई नहरें टूट गई हैं। होशियारपुर में टांडा उड़मुड़ के सलेमपुर मंड क्षेत्र में ब्यास दरिया की बाढ़ में एक व्यक्ति के डूबने से मौत हो गई। जलालपुर निवासी जैला अपने दो साथियों के साथ बयास नदी की बाढ़ में फंसे कुछ लोगों की मदद करने के लिए पानी में उतरा था।

बिहार में नेपाल सीमा से घुसे जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकी, हाईअलर्ट जारी

एजेंसी

पटना। बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य में पाकिस्तान स्थित संगठनों के आतंकवादियों के प्रवेश की खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद राज्यव्यापी हाई अलर्ट जारी कर दिया। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, आतंकी समूह जैश-ए-मोहम्मद के तीन संदिग्ध सदस्य नेपाल सीमा पार करके बिहार में घुसे हैं। बिहार पुलिस की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार, संदिग्धों की पहचान रावलपिंडी के हसनैन अली, उमरकोट के आदिल हुसैन और बहावलपुर के मोहम्मद उस्मान के रूप में हुई है। खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि वे अगस्त के दूसरे सप्ताह में काठमांडू पहुंचे थे और पिछले सप्ताह बिहार में प्रवेश किया था। बिहार पुलिस

मुख्यालय ने सीमावर्ती जिलों की पुलिस के साथ संदिग्धों के पासपोर्ट संबंधी विवरण साझा किए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को निगरानी बढ़ाने और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला खुफिया इकाइयों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है बिहार में ऑपरेशन सिंदूर और इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मई में भारत-नेपाल सीमा और सीमांचल जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। बिहार में मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, किशनगंज जिलों सहित सीमावर्ती इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। बिहार नेपाल के साथ लगभग 729 किलोमीटर लंबी खुली सीमा साझा करता है। लंबे समय से घुसपैठ और सीमा पार से आवाजाही का प्रमुख केंद्र बन गया है। राज्य के सात जिले इस खुली सीमा पर स्थित हैं, जो निरंतर निगरानी और सुरक्षा प्रवर्तन के लिए बड़ी चुनौतियां पेश करते हैं।

रेलवे बोर्ड चेयरमैन व सीईओ सतीश कुमार का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ा

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सतीश कुमार का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के स्थापना अधिकारी कार्यालय द्वारा आज जारी आदेश के अनुसार मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति (एसीसी) ने भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (आईआरएमएस) से सेवानिवृत्त सतीश कुमार के कार्यकाल विस्तार को मंजूरी दी है। वह 01 सितम्बर 2025 से एक वर्ष तक अनुबंध के आधार पर, मौजूदा शर्तों और नियमों पर कार्यरत रहेंगे या फिर अगले आदेश तक पद पर बने रहेंगे। कुमार वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। आदेश की प्रतियां प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई हैं।

बिहार की जनता होशियार, कटे वोट फिर जोड़े भी जाएंगे : राहुल गांधी

एजेंसी

सीतामढ़ी । लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी गुरुवार को 'वोटर अधिकार यात्रा' के क्रम में सीतामढ़ी पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार में एसआरआई के जरिए काटे गए नामों को लेकर चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने कहा कि ये अभी वोट काटे गए हैं लेकिन नए नाम जोड़े भी जाएंगे। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर वोट का अधिकार समाप्त हो गया या वोट कट जाएगा तो गरीबों के पास कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अभी वोट काटा जा रहा है, उसके बाद राशन कार्ड समाप्त किया जाएगा और उसके बाद जमीन छीन ली जाएगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में

वोट चोरी कर सत्ता में पहुंचे हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में हमारे गठबंधन को अधिक सीटें आई, लेकिन चार महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में हमारा गठबंधन दिखा तक नहीं।उन्होंने आरोप लगाया कि यहां लाखों नाम जोड़कर वोट चोरी की गई। कांग्रेस नेता ने बिहार में इस यात्रा की शुरुआत करने के उद्देश्य को लेकर कहा कि चुनाव आयोग को यह पता चल जाए कि बिहार की जनता होशियार है। उन्होंने संविधान की चर्चा करते हुए कहा कि आजादी के पहले दलित को अछूत कहा जाता था। आजादी के बाद संविधान के जरिए उन्हें अधिकार दिए गए हैं।उन्होंने दावा किया कि बिहार की मतदाता सूची से जो 65 लाख नाम काटे गए हैं, उनमें दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, और किसान शामिल हैं, इसमें एक अमीर का नाम नहीं है। ये गरीबों का अधिकार छीनना चाहते हैं।

जम्मू-कश्मीर के उरी में दो आतंकवादी मारे गए, घुसपैठ की कोशिश नाकाम

एजेंसी

श्रीनगर । जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर घुसपैठ की कोशिश को सेना ने गुरुवार को नाकाम कर दिया, जिसमें दो आतंकवादी मारे गए अधिकारियों ने बताया कि गुरेज सेक्टर में नौशहरा नार्द के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान दो आतंकवादी मारे गए। इलाके में अभी तलाशी अभियान चल रहा है।

इससे पहले, 25 अगस्त को संयुक्त बलों ने बारामूला के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम कर दिया। उरी सेक्टर के तोरणा इलाके में आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जब नियंत्रण रेखा पर तैनात सैनिकों ने संदिग्ध

गतिविधि देखी। घुसपैठियों को चुनौती दी गई, जिसके बाद दोनों ओर से कुछ देर तक गोलीबारी हुई। इसके बाद इलाके में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी आतंकवादी नियंत्रण रेखा पार करके भारतीय सीमा में घुसने में कामयाब न हो पाए। वहीं, 13 अगस्त को उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास सेना के साथ मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया था, जब आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे जम्मू-कश्मीर में संयुक्त बलों ने आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने शुरू किए हैं, जिसमें आतंकियों, उनके सहयोगियों (ओजीडब्ल्यू) और समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है। इन अभियानों का मकसद केवल हथियारबंद आतंकियों को खत्म करना नहीं, बल्कि पूरे आतंकी तंत्र को ध्वस्त करना है।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा नियमित रूप से सुरक्षा समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, जिसमें उनका ध्यान आतंकवाद के पूरे ढांचे को तोड़ने पर है। हवाला धन रैकेट, ड्रग तस्करी और नशीली दवाओं के कारोबार पर भी संयुक्त बलों की कड़ी नजर है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इनसे मिलने वाला पैसा आतंकवाद को बढ़ावा देने में इस्तेमाल होता हैखुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों ने कई हवाला रैकेट और ड्रग तस्करी के नेटवर्क को पकड़ा है, जिनके तार सीमा पार बैठे आतंकी सरगनाओं से जुड़े थे। इसीलिए संयुक्त बल हवाला रैकेट और ड्रग तस्करी जैसी गतिविधियों को प्राथमिकता के साथ निशाना बना रहे हैं, साथ ही हथियारों का इस्तेमाल करने वाले आतंकियों से भी निपट रहे हैं।

एनएचआरसी ने गाजियाबाद की गैंगरेप पीड़िता की मौत पर लिया स्वतः संज्ञान

एजेंसी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मूक-बधिर लड़की के साथ हुए गैंगरेप और उसकी मौत की खबर का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले में यूपी के पुलिस डीजीपी और गाजियाबाद के जिलाधिकारी को नोटिस भेजकर दो हफ्ते के अंदर पूरी रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में अब तक की जांच और मुआवजे के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। मानवाधिकार आयोग के अनुसार, आयोग को एक मीडिया रिपोर्ट्स में 18 अगस्त को गाजियाबाद के लोनी इलाके में दो लोगों ने इस मूक-बधिर लड़की से गैंगरेप की जानकारी मिली। इसके तीन दिन बाद, 21 अगस्त को वह अपने घर पर मृत पाई गई। बताया जा रहा है कि उसका इलाज दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज में चल रहा था। आयोग ने कहा है कि अगर मीडिया में आई ये खबरें सही हैं, तो ये मामला गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन का है। इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों से जल्द से जल्द पूरी जानकारी देने को कहा गया है।

दीपक कुमार अभिषेक जदयू विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत

नई दिल्ली/पटना। पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक कुमार अभिषेक को जनता दल (यूनाइटेड) जदयू विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनित किया गया है। जनता दल (यूनाइटेड) जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद की अनुशंसा पर जदयू विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ आनंद कुमार ने दीपक कुमार अभिषेक को जदयू विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतिश कुमार का हृदय से आभार व्यक्त करने के साथ-साथ संगठन की मजबूती के लिए पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ काम करने की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कीद्य डॉ आनंद कुमार ने दीपक कुमार अभिषेक को प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपने के बाद उन्हें जदयू का समर्पित कार्यकर्ता बताया। उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि दीपक अभिषेक जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदर्श के अनुरूप कार्य करेंगे एवं दल की नीति, कार्यक्रमों एवं विचारों को जन-जन तक पहुंचने में कारगर भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पवन कुमार, शंभू कुमार, अमर कुमार एवं वरुण कुमार भी उपस्थित रहे।

आईजीएल सड़कों की मरम्मत का काम जल्द करें शुरू : रविंद्र इंद्राज

नई दिल्ली। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने बवाना में गैस पाइपलाइन के चल रहे कार्यों की वजह से सड़कों की मरम्मत के अधूरे पड़े कामों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है, वहां सड़कों की मरम्मत का कार्य तुरंत शुरू करें। विशेषकर अनधिकृत कॉलोनियों में गड्ढों को भरकर सड़कों की समुचित मरम्मत की जाए। वहीं, अन्य क्षेत्रों में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के माध्यम से सड़क के कार्य पूरे कराए जाएं।बैठक में आईजीएल, एमसीडी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा डीएसआईडीसी के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि जिन इलाकों में पाइपलाइन का कार्य अभी प्रगति पर है, वहां आईजीएल संबंधित विभागों एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग व डीएसआईडीसी के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करे ताकि आमजन को बार-बार सड़कों की खुदाई से परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि पाइप लाइन बिछाने, नालों के निर्माण, सड़कों के निर्माण, सीवर लाइन बिछाने की परियोजनाओं पर आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने से ही ऐसा संभव हो पाएगा।

दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान के तहत निगम ने करोल बाग में साइक्लोथॉन का किया आयोजन

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के करोलबाग जोन में दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान के तहत साइक्लोथॉन का आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों, युवा साइकिल प्रेमियों और समाजसेवियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में दिल्ली के उपमहापौर जय भगवान यादव, स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा और विधायक उमंग बजाज उपस्थित रहे। इस साइक्लोथॉन का उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के महत्व के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर उपमहापौर जय भगवान यादव ने कहा कि दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान प्रधानमंत्री की स्वच्छ भारत मिशन पहल को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। उन्होंने जनता से अपील की कि वे न केवल अपने घरों में बल्कि आसपास के इलाकों में भी स्वच्छता बनाए रखने की जिम्मेदारी लें। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में योगदान करते हुए एक पेड़ अपनी मां के नाम अवश्य लगाना चाहिए।उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे ताकि नागरिकों की जागरूकता और भागीदारी निरंतर बनी रहे।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार आपसी इच्छा से होना चाहिए, दबाव में नहीं : भागवत

एजेंसी

नई दिल्ली । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि भारत को स्वदेशी को प्राथमिकता देते हुए आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम बढ़ाने होंगे। सरसंघचालक ने इस बात जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार आपसी इच्छा से होना चाहिए, दबाव में नहीं।

डॉ. भागवत विज्ञान भवन में चल रहे तीन दिवसीय व्याख्यान शृंखला '100 वर्ष की संघ यात्रा = नए क्षितिज' के दूसरे दिन संबोधित कर रहे थे। यह कार्यक्रम संघ की शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया है। डॉ. भागवत ने कहा कि आत्मनिर्भरता ही सब समस्याओं का समाधान है और इसी में स्वदेशी की सार्थकता निहित है। आत्मनिर्भर होने का मतलब आयात बंद करना नहीं है। दुनिया चलती है क्योंकि यह एक-दूसरे पर निर्भर है। इसलिए आयात-निर्यात जारी रहेगा। हालांकि, इसमें कोई दबाव नहीं होना

चाहिए। उन्होंने कहा, अपना देश आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसके लिए स्वदेशी के उपयोग को प्राथमिकता दें। देश की नीति में स्वेच्छा से अंतरराष्ट्रीय व्यवहार होना चाहिए, दबाव में नहीं। यही स्वदेशी है।÷ उन्होंने कहा कि केवल आवश्यक वस्तुओं का ही आयात किया जाना चाहिए बाकी सभी वस्तुओं का उत्पादन देश में ही होना चाहिए। सरसंघचालक ने बताया कि संघ स्वयंसेवक भविष्य में 'पंच परिवर्तन' यानी समाज परिवर्तन के पांच कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इनमें संस्कारात्मक अनुभव शामिल है, जिसके अंतर्गत बच्चों को वास्तविक जीवन से परिचित कराने की बात कही गई। उन्होंने कहा, ÷बच्चों को पेरिस ले जाने के बजाय कारगिल, झुग्गी-बस्तियों और ग्रामीण जीवन दिखाना चाहिए ताकि वे समाज की सच्चाई समझ सकें।÷ उन्होंने इसके तहत 'कुटुंब प्रबोधन' की अवधारणा रखते हुए कहा कि प्रत्येक परिवार को बैठकर सोचना चाहिए कि वे भारत के लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ÷पौधा लगाने से लेकर वंचित वर्ग के बच्चों को पढ़ाने तक कोई भी छोटा कार्य देश और समाज से जुड़ने का भाव पैदा करता है। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि केवल चर्चा करने से बदलाव संभव नहीं है। डॉ. भागवत ने कहा, 'छोटे-छोटे प्रयास करना जरूरी है, जैसे पौधा लगाना, जल संरक्षण करना और प्लास्टिक का कम उपयोग करना। इसी से वास्तविक परिवर्तन आएगा।' भागवत ने इसी में सामाजिक समरसता के महत्व को रेखांकित किया।

भारत को समुद्री परिवहन में अग्रणी बनाने के लिए आईएमडब्ल्यू एक बड़ा अवसरः रामचंद्रन

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय समुद्री सप्ताह 2025 (आईएमडब्ल्यू) की तैयारियों को लेकर बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय की शीर्ष समिति की बैठक में दूसरे देशों की भागीदारी बढ़ाने, भारत की समुद्री क्षमताओं के वैश्विक प्रदर्शन और आईएमडब्ल्यू को साझेदारी के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच बनाने जैसे विषयों पर चर्चा की गयी। मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैठक की जानकारी साझा की। इसके मुताबिक बैठक की अध्यक्षता मंत्रालय के सचिव टीके रामचंद्रन ने की। इसमें मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, देश के प्रमुख बंदरगाहों के अध्यक्ष और संबंधित संगठनों के प्रमुख शामिल हुए। रामचंद्रन ने सभी अधिकारियों से विस्तृत जानकारी लेते हुए कहा कि भारत को समुद्री परिवहन में अग्रणी बनाने के लिए आईएमडब्ल्यू 2025 एक बड़ा अवसर है, जिसे पूरी तैयारी के साथ भव्य और प्रभावशाली बनाना होगा। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि आयोजन को सिर्फ एक समारोह

तक सीमित न रखते हुए इसे रणनीतिक वैश्विक साझेदारी, निवेश आकर्षण और नवाचार के मंच के रूप में स्थापित किया जाए। उल्लेखनीय है कि भारतीय समुद्री सप्ताह 2025 अक्टूबर के अंत में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान भारत के समुद्री व्यापार, नौवहन और बंदरगाह विकास पर चर्चा के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाकर भारत को वैश्विक समुद्री नेतृत्व की दिशा में आगे ले जाने के प्रयास किए जाएंगे।

भारत-नेपाल हिमालयी लोक संस्कृति परिषद दिसंबर में हल्द्वानी में वार्षिक संगोष्ठी आयोजित करेगी

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत-नेपाल हिमालयी लोक संस्कृति परिषद आगामी दिसंबर माह में उत्तराखंड के हल्द्वानी (नैनीताल) में वार्षिक संगोष्ठी का आयोजन करेगी। इस बार संगोष्ठी में पर्यावरण एवं लोक संस्कृति संरक्षण में महिलाओं की भूमिका पर विशेष फोकस रहेगा। परिषद ने यहां प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी। इस अवसर पर भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक सहयोग, हिमालय क्षेत्र की परंपराओं और पर्यावरण संरक्षण पर विचार-विमर्श हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पटपड़गंज विधानसभा के विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने कहा कि भारत और नेपाल केवल पड़ोसी राष्ट्र नहीं, बल्कि साझा संस्कृति, आस्था और परंपराओं से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिमालय हमें न केवल भौगोलिक दृष्टि से जोड़ता है, बल्कि यह पीढ़ियों की सांस्कृतिक स्मृतियों और लोककथाओं का भी आधार है। नेगी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन हमारी पहचान को सशक्त करते हैं और आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कार्यक्रम के

आयोजन के लिए भारत-नेपाल हिमालयी लोक संस्कृति परिषद की सराहना की।इस अवसर पर नेपाल की लोकगायिका इब्सल संजयाल और उत्तराखंड रानीखेत की जिला पंचायत सदस्य शांति उप्रेती को उनके विशिष्ट योगदान के लिए विशेष हिमालय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया।इब्सल संजयाल ने अपनी संस्कृति और लोकगायन की परंपरा के महत्व को रेखांकित करते हुए महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अपनी सक्रिय भूमिका का उल्लेख किया। शांति उप्रेती ने जैविक खेती, ग्राम्य विकास और हिमालयी पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर अपने विचार रखते हुए कहा कि उत्तराखंड और नेपाल की संस्कृति एक-दूसरे की पूरक हैं और इसी आपसी सहयोग से ही हिमालय की धरोहर को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंच सकते हैं।

'वीर विट्ठलभाई की गौरव गाथा' प्रदर्शनी का विधायक अपने क्षेत्रों में प्रचार करें : विजेंद्र गुप्ता

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय संसद के 100 गौरवशाली वर्षों के उपलक्ष्य में दिल्ली विधानसभा परिसर में आयोजित विशेष प्रदर्शनी 'वीर विट्ठलभाई की गौरव गाथा' को जनता के लिए खोल दिया गया। उद्घाटन के कुछ ही दिनों में यह प्रदर्शनी छात्रों, परिवारों, विद्वानों और नागरिकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सभी विधायकों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रदर्शनी का प्रचार करें ताकि अधिकतम नागरिक, विशेष रूप से स्कूल और कॉलेज के छात्र-छात्राएं, इसका लाभ उठा सकें एवं भारत की संसदीय विरासत को गहराई से समझ सकें। छात्रों और युवाओं ने प्रदर्शनी में विशेष उत्साह दिखाया। वे विट्ठलभाई पटेल की प्रतिमा एवं ऐतिहासिक विधानसभा भवन के साथ तस्वीरें खींचते नजर आए। विशेष रूप से बनाए गए सेल्फी प्वॉइंट्स-'इतिहास का एक पल' और 'आजादी की आवाजें'- युवाओं के बीच लोकप्रिय हो गए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मदन मोहन मालवीय और गोपाल कृष्ण गोखले की जीवंत प्रतिमाओं के साथ तस्वीरें

खिंचवाकर लोग इस ऐतिहासिक क्षण को संजो रहे हैं। इतिहास के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए यह प्रदर्शनी एक खजाने के समान है। इसमें महात्मा गांधी, विट्ठलभाई पटेल और स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य महान नेताओं के बीच आदान-प्रदान हुए दुर्लभ पत्र, भाषण और अभिलेखीय तस्वीरें शामिल हैं। ये अनमोल धरोहरें दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार से विशेष रूप से लाई गई हैं और पहली बार जनता के सामने प्रदर्शित की जा रही हैं। यह अवसर नागरिकों को भारत की लोकतांत्रिक यात्रा और विधानसभा भवन की समृद्ध धरोहर को गहराई से समझने का अवसर प्रदान कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि यह प्रदर्शनी केवल इतिहास दिखाती ही नहीं बल्कि उसे अनुभव कराने का अवसर भी देती है। अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी (वीआर) जोन, स्वतंत्रता सेनानियों की जीवंत प्रतिमाएं, दुर्लभ दस्तावेज, और भारत की लोकतांत्रिक यात्रा पर आधारित विशेष डॉक्यूमेंट्री, सभी आयु वर्ग के दर्शकों के लिए सीखने और जानने का अद्भुत अनुभव प्रस्तुत कर रहे हैं। यह प्रदर्शनी 31 अगस्त प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से सायं 06 बजे तक दिल्ली विधानसभा परिसर में जनता के लिए खुली रहेगी।

भारत की ताकत उसके खेतों में हैः शिवराज सिंह

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत की ताक़त उसके खेतों में है, भारत की गति उसके गांवों में है, भारत का आत्मविश्वास किसान के श्रम में है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए अपने संदेश में कहा कि हमारे अन्न के भंडार भरे हैं, हम अपनी जरूरतें पूरी करने में तो सक्षम हैं ही, विश्व का 'फूड बास्केट' भी बन रहे हैं। गेहूं और मक्का का रिकॉर्ड उत्पादन सिर्फ आंकड़ा नहीं है, किसानों के परिश्रम की विजय है। शिवराज सिंह ने कहा कि हम केवल उत्पादन नहीं कर रहे, हम दुनिया को यह बता रहे हैं कि भारतीय किसान आने वाले युग का नेतृत्व करने को तैयार है। गांव की हमारी बहनें, लखपति दीदी के रूप में अर्थव्यवस्था को नई गति दे रही हैं। उनके हाथों में आत्मनिर्भरता का स्वप्न है, उनके श्रम में समृद्धि का

संकल्प है। उनके सामर्थ्य से गांव नवाचार और उद्यमिता का केंद्र बन रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बदल रहे हैं, हम संकल्प से सिद्धि की ओर जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस पोस्ट को अमेरिका के 50 प्रतिशत टैरिफ से जोड़कर देखा जा रहा है। शिवराज ने लिखा कि भारत सक्षम है, आत्मविश्वास से भरा है। ज़िंदगी को वही गढ़ते हैं, जो शिलाएं तोड़ने का साहस रखते हैं। आज का भारत वही है, जो चुनौतियों को अवसर में बदलना जानता है, जो कठिनाइयों से जूझकर और निखरता है। आज का भारत आत्मविश्वास से भरा है, आज का भारत सक्षम है, आज का भारत अपना रास्ता खुद बनाना जानता है। हम आगे बढ़ रहे हैं, और भी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। रास्ते की कोई भी रुकावट इतनी बड़ी नहीं कि हमें रोक सके। भारत ने विज्ञान में नई ऊंचाइयां छुई हैं। चंद्रयान-3 ने चांद पर कदम रखा, आदित्य-एल1 सूर्य का रहस्य जान रहा है। हमारी गगनयान यात्रा सितारों की ओर उड़ान भरने को तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि भारत कृषि में नए प्रयोग कर रहा है, डिजिटल भुगतान में दुनिया को राह दिखा रहा है, स्टार्टअप और नवाचार से युवाओं का आत्मविश्वास बुलंद कर रहा है। खेती में किसान का परिश्रम, सीमा पर जवान का शौर्य, प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक का ज्ञान, और कारखानों निर्माण स्थलों पर श्रमिकों का पसीना इन्हीं के बल पर नया भारत आकार ले रहा है।

खेलों में भारत का परचम लहरा रहा है, ओलंपिक और विश्व प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ी स्वर्णिम अध्याय लिख रहे हैं। विश्व मंच पर भारत की आवाज बुलंद है। जी20 की अध्यक्षता से लेकर 'वसुधैव कुटुम्बकम' के मंत्र तक भारत पूरी दुनिया को जोड़ने वाला पुल बन चुका है। हर क्षेत्र में भारत अपनी क्षमता साबित कर रहा है।

पंजाब में बाढ़ को लेकर भाजपा ने मुख्यमंत्री मान पर बोला हमला

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी नेतृत्व पर करारा प्रहार किया। पार्टी ने कहा कि जब रोम जल रहा था, तब नीरो बंसी बजा रहा था। वही त्रासदी आज पंजाब में दोहराई जा रही है। हज़ारों परिवार बाढ़ में फंसे हुए हैं और मुख्यमंत्री मान तमिलनाडु में हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पंजाब के संसाधनों पर दावत उड़ा रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने एक बयान में कहा कि झूठे वादों की बजाय मान को जवाब देना चाहिए कि किसानों को कर्ज़ माफ़ी कब मिलेगी? एमएसपी टॉप-अप कब पूरा होगा? पंजाब की महिलाएं पिछले 40 महीनों से 1000 रुपये प्रति माह का इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार ने अब तक एक भी घोषणा पूरी नहीं की। उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों में मान सरकार ने पंजाब पर एक लाख करोड़ रुपये का नया कर्ज़ लाद दिया है, केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे- पीएम पोषण योजना को अपनी फोटो लगाकर पेश किया है और फिर भी मूल वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि आज पंजाब के 20 लाख से अधिक बच्चे और देशभर के 11.5 करोड़ से अधिक बच्चे केवल पीएम पोषण योजना की वजह से पोषण पा रहे हैं। मुख्यमंत्री मान की नाकामी को पंजाब की बदहाली के लिए ज़िम्मेदार ठहराते हुए चुग ने कहा कि कानून-व्यवस्था चरमरा चुकी है। अर्थव्यवस्था पंगु हो चुकी है ।

विकसित भारत का सपना शिक्षकों की मेहनत और मार्गदर्शन के बिना पूरा नहीं हो सकता : आशीष सूद

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि विकसित भारत का सपना शिक्षकों की तपस्या, मेहनत और मार्गदर्शन के बिना पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने बाल भारती स्कूल पूसा रोड की चाइल्ड एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्यातिथि के रूप में भाग लेते हुए यह बात कही। इस कार्यक्रम में पद्मश्री आनंद कुमार(सुपर 30) के साथ स्कूल की कार्यकारिणी प्रिंसिपल और बच्चे भी उपस्थिति रहे।मंत्री सूद ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि समय के साथ शिक्षकों की चुनौतियां भी बदली हैं। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड से लेकर कंप्यूटर और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक से शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार आया है। आज हम एआई बेस्ड शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों की मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक योग्यता को बढ़ाना ही है। उन्होंने सभी सम्मानित शिक्षकों और पुरस्कार प्राप्त करने वालों को बधाई दी। सूद ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार निजी और सरकारी दोनों स्कूलों को अपना मानती है।

निजी स्कूलों के साथ कोई टकराव या मतभेद नहीं है, परंतु सरकार के लिए मध्यवर्गीय अभिभावकों के हितों की रक्षा के लिए फीस विनियमन कानून लागू करना आवश्यक था, जिसको सरकार ने लागू भी किया है।

मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को विश्वस्तरीय बनाने का जो संकल्प लिया है, उस पर कई स्तरों पर काम किया जा रहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार इस वर्ष 75 सीएमश्री स्कूल बना रही है। इन स्कूलों में कई तरह की उन्नत तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इन स्कूलों में अब्दुल कलाम लैंग्वेज लैब होगी, एआई युक्त स्मार्ट क्लास होंगे, एआई बेस्ड अटेंडेंस की व्यवस्था, साइंस लैब्स, इंटरैक्टिव पैनल्स सहित बुनियादी और आधुनिक सुविधाएं होगी। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी से हम मुंह नहीं मोड़ सकते बल्कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर हम देश और समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। कृत्रिम मेधा के बारे में मंत्री ने कहा की एआई का सफल प्रयोग ही एक सफल समाज की कुंजी है।

ठगी के मामले में आरोपित गिरफ्तार

नई दिल्ली।दिल्ली के शाहदरा जिले की साइबर थाना पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश कराने के नाम पर युवक से करीब पांच लाख रुपये ठगी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। शाहदरा जिले के पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम के मुताबिक पकड़े गए आरोपित की पहचान ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर निवासी शुभम जैन (32) के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल मोबाइल फोन व सिमकार्ड बरामद किया है।शुभम ने अपने करीबी दोस्त के कहने पर एक फर्जी कंपनी बनाकर करंट अकाउंट खोला। इसी में ठगी की रकम को ट्रांसफर किया गया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि शुभम के खाते में दो माह के दौरान एक करोड़ 17 लाख रुपये की रकम का लेनदेन हुआ है। पुलिस शुभम के दोस्त व बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस उपायुक्त गौतम ने बताया कि ओल्ड अनारकली, शाहदरा निवासी कृष्णा कुमार ने साइबर थाने में 4.97 लाख रुपये ठगी की शिकायत दी थी।

कटरा भूस्खलन में 32 मृतकों के परिवारों को 9-9 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान

एजेंसी

जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कटरा में हुए भूस्खलन की घटना के 32 मृतकों के परिवारों को 9-9 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बात की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तत्परता से राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उपराज्यपाल ने आज कटरा स्थित एसएमवीडी नारायण सुपरस्पेशलिटी अस्पताल जाकर भूस्खलन में घायल हुए श्रद्धालुओं से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।

उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि श्राइन बोर्ड की नीति के अनुसार 5 लाख रुपये दिए जाते हैं और आपदा प्रबंधन विभाग भी मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपये प्रदान करेगा। उपराज्यपाल ने कहा कि कटरा भूस्खलन की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कल दोपहर बादल फटने के कारण यात्रा स्थगित कर दी गई थी, लेकिन अर्धकुंवारी के पास बादल फटने के कारण कई लोग पानी के बहाव में बह गए। उन्होंने कहा कि कई अनमोल जानें गईं और कई घायल हुए। उन्होंने कहा कि कई

मृतकों की पहचान हो गई है और उनके शवों को घर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। कटरा स्थित एसएमवीडी नारायण सुपरस्पेशलिटी अस्पताल जाकर भूस्खलन में घायल हुए श्रद्धालुओं से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। डॉक्टरों से सर्वोत्तम संभव उपचार सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने आपातकालीन सेवाकर्मियों, एसएमवीडीएसबी कर्मचारियों और नागरिकों के प्रति कृतज्ञता जताई, जिनके अनुकरणीय प्रयासों से कई लोगों की जान बच गई। उपराज्यपाल सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बाढ़ की स्थिति से अवगत कराया है। विभिन्न जिलों में राहत एवं बचाव कार्य जारी है और मैंने अधिकारियों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखने और अपने-अपने पदों पर कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

उपराज्यपाल ने जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और बाढ़ की स्थिति तथा बचाव एवं राहत कार्यों का जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है, वहां प्राथमिकता के आधार पर बिजली, संचार और जल आपूर्ति बहाल की जाए। निचले बाढ़ग्रस्त इलाकों से 5000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, मंडलायुक्त कार्यालय के साथ समन्वय में काम कर रहे हैं और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। भारतीय सेना ने एक बयान में बताया कि जम्मू और पठानकोट क्षेत्रों में आई भीषण बाढ़ से निपटने के लिए राहत एवं बचाव अभियानों में 13 बाढ़ राहत और बचाव टुकड़ियां तैनात की गई हैं।

'दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 2025' विद्यार्थी के शिक्षा के अधिकार को सशक्त करेगाः आशीष सूद

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 'दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025' शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक मील का पत्थर है। विद्यालयों में मनमाने शुल्क निर्धारण पर रोक लगाते लिए यह कानून अभिभावकों को राहत प्रदान करेगा और विद्यार्थी के शिक्षा के अधिकार को सशक्त करेगा। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने यह विचार दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी में दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 पर आयोजित एक विशेष व्याख्यान सत्र में व्यक्त किए। शिक्षा मंत्री ने यहां छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि कि दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस वृद्धि पर रोक लगाने के लिए दिल्ली निजी स्कूल फीस विनियमन विधेयक-2025 विधानसभा में पेश किया था जो अब स्वीकृति के बाद कानून का रूप ले चुका है। इसका उद्देश्य शिक्षा को केवल एक सेवा नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व और समान अवसर का माध्यम बनाना है। शिक्षा मंत्री ने विश्वास जताया कि यह अधिनियम शिक्षा के क्षेत्र में विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ाएगा और अभिभावकों और विद्यार्थियों दोनों के हितों की रक्षा करेगा। उन्होंने दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 का उल्लेख करते हुए कहा की उस कानून में केवल 300 प्राइवेट स्कूल (जिन्होंने ष्ठ्ठ से जमीन ली थी) को रेगुलेट करने का ही प्रावधान था। जिस कारण अन्य स्कूलों पर कोई कार्यवाही नहीं होती थी। उन्होंने यह भी बताया की दिल्ली में समय के साथ प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़कर आज लगभग 1700 हो चुकी है, जिनमें 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन फीस बढ़ाने के लिए 300 स्कूलों पर ही कार्यवाही होती है। लेकिन अब दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम 2025 के लागू होने की बाद अब सभी 1700 प्राइवेट स्कूलों पर सरकार का आदेश लागू होगा, केवल डीडीए लैंड क्लॉज वाले स्कूलों पर नहीं। नए कानून के अनुसार अब सभी निजी स्कूल इसके दायरे में आ गए है। शिक्षा मंत्री सूद ने बताया कि दिल्ली विधानसभा में 8 अगस्त को यह शिक्षा विधेयक पारित किया गया। इसके बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की स्वीकृति के साथ दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम 2025 लागू हो गया।

संपादकीय

डिजिटल जुनून और युवा हिंसा: समाज के सामने गंभीर चुनौती

समाज का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी होती है। यदि युवा सशक्त, जागरूक और जिम्मेदार हों, तो किसी भी राष्ट्र को प्रगति और समृद्धि से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि यही ऊर्जा गलत दिशा में मुड़ जाए, तो वही युवा समाज और राष्ट्र के लिए चुनौती भी बन सकते हैं। दुर्भाग्य से आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ विज्ञान और तकनीक ने भले ही अभूतपूर्व तरक्की कर ली हो, लेकिन मानवीय मूल्य, संवेदनशीलता और नैतिकता धीरे-धीरे कमजोर पड़ते जा रहे हैं। इसका सबसे प्रत्यक्ष और चिंताजनक असर युवाओं के भीतर पनप रही हिंसक प्रवृत्तियों में दिखाई देता है।

पिछले कुछ वर्षों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिन्होंने हमें झकझोर कर रख दिया है। कभी किसी स्कूल के टिफिन बॉक्स से चाकू निकलता है, कभी छोटी-सी कहासुनी पर जानलेवा हमला हो जाता है, तो कभी शिक्षकों तक को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। हाल ही में हरियाणा में एक युवा शिक्षक की हत्या की घटना ने समाज को गहरी सोच में डाल दिया है। ये घटनाएँ केवल आपराधिक समाचार नहीं हैं, बल्कि इस बात का संकेत हैं कि हमारी युवा पीढ़ी एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है।

आज का युवा डिजिटल दुनिया से घिरा हुआ है। स्मार्टफोन और इंटरनेट उनकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। ऑनलाइन गेम्स, जिनमें मारपीट और हिंसा को रोमांचक और मनोरंजक बनाकर प्रस्तुत किया जाता है, युवाओं के मनोविज्ञान पर गहरा असर डाल रहे हैं। युवाओं में बढ़ती हिंसा का एक बड़ा कारण डिजिटल प्लेटफॉर्म और गेमिंग ऐप्स पर आसानी से उपलब्ध हिंसक व अश्लील कंटेंट है। सरकार ने समय-समय पर इस दिशा में कदम उठाए हैं। कई बार ऐसे मोबाइल गेम्स और ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिनमें अत्यधिक हिंसा, नशे या असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता था। हाल ही में कुछ ऑनलाइन गेम्स को इस आधार पर प्रतिबंधित किया गया कि वे बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रहे थे और उनमें आत्मघाती प्रवृत्तियों को उकसाने वाली सामग्री मौजूद थी। हालांकि, केवल प्रतिबंध ही स्थायी समाधान नहीं है। सरकार को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए सख़्त गाइडलाइंस और प्रभावी मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार करना होगा, ताकि युवाओं को सुरक्षित और सकारात्मक कंटेंट ही उपलब्ध कराया जा सके। साइबर नियामक ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ डिजिटल साक्षरता पर भी ध्यान देना होगा, ताकि माता-पिता और बच्चे दोनों यह समझ सकें कि कौन-सा कंटेंट सुरक्षित है और कौन-सा हानिकारक। कई बार बच्चे और किशोर इन खेलों के पात्रों से इतना जुड़ जाते हैं कि वास्तविक जीवन में भी उसी तरह का व्यवहार करने लगते हैं। जब आभासी हिंसा आदत बन जाती है, तो संवेदनशीलता और करुणा धीरे-धीरे खत्म होने लगती है। इसके अलावा, इंटरनेट पर बिना किसी नियंत्रण के अश्लील और हिंसक सामग्री की उपलब्धता ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि डिजिटल युग ने जहाँ ज्ञान और अवसरों की दुनिया खोली है, वहीं उसने हिंसा और नैतिक पतन का रास्ता भी आसान कर दिया है।

युवाओं के हिंसक व्यवहार का एक बड़ा कारण पारिवारिक वातावरण की कमी भी है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में माता-पिता अपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते। कामकाजी जीवन की व्यस्तता और भौतिक सुख-सुविधाओं की होड़ में बच्चों की भावनात्मक जरूरतें पीछे छूट जाती हैं। बच्चे जब अपने माता-पिता से भावनात्मक रूप से दूर होते हैं, तो वे सही-गलत का फर्क समझाने वाले मार्गदर्शक से वंचित हो जाते हैं। कभी पारिवारिक वातावरण बच्चों को नैतिकता, धैर्य और सहनशीलता सिखाता था। संयुक्त परिवार व्यवस्था में बच्चे अपने दादा-दादी और बड़ों से जीवन के मूल्य सीखते थे। लेकिन अब जब परिवार छोटे और व्यस्त होते जा रहे हैं, तो बच्चे अपने अकेलेपन और असुरक्षा से जूझते हुए गलत संगत या गलत रास्तों की ओर बढ़ जाते हैं। यही अकेलापन कई बार उन्हें हिंसा का सहारा लेने के लिए प्रेरित करता है।

आज का समाज सफलता को सबसे बड़ी कसौटी मान बैठा है। हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा स्कूल, कॉलेज, नौकरी या व्यवसाय में सबसे आगे निकले। प्रतियोगिता की यह दौड़ युवाओं पर अस्वाभाविक दबाव डाल रही है। नतीजा यह होता है कि युवा अधीर हो गए हैं। उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए, वे शॉर्टकट अपनाने लगते हैं और असफल होने पर निराशा से भर जाते हैं। यह निराशा धीरे-धीरे आक्रामकता और हिंसक प्रवृत्तियों का रूप धारण कर लेती है। यह स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने बच्चों को केवल सफल बनाना चाहते हैं, या उन्हें संवेदनशील और जिम्मेदार इंसान भी बनाना चाहते हैं।

यह मानना गलत होगा कि केवल कानून और व्यवस्था से इस समस्या का समाधान हो सकता है। पुलिस और अदालतें अपराध रोक सकती हैं, लेकिन अपराध की जड़ें वहीं पनपती हैं जहाँ परिवार, समाज और शिक्षा कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि समाज के हर वर्ग को मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा। माता-पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों से संवाद करें, उनके मित्र बनें और उनके ऑनलाइन व्यवहार पर नजर रखें। बच्चों को सिखाना होगा कि डिजिटल दुनिया में हर चीज पर आँख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। शिक्षा संस्थानों की भी बड़ी जिम्मेदारी है। स्कूल और कॉलेज केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं होने चाहिए, बल्कि वहाँ नैतिक शिक्षा, जीवन कौशल और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों को खेल, कला और साहित्य जैसी रचनात्मक गतिविधियों में जोड़ना चाहिए, ताकि उनकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगे।

गणेश हैं विघ्नहर्ता-मंगलकर्ता एवं जीवंत राष्ट्रीयता के प्रतीक

भारतीय संस्कृति और धर्मजगत में गणेशजी का स्थान अद्वितीय है। वे विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता, मंगलकर्ता और उन्नत राष्ट्र-निमार्ता हैं। वे न केवल भारतीय संस्कृति एवं जीवनशैली के कण-कण में व्याप्त है बल्कि विदेशों में भी घर-कारों-कार्यालयों एवं उत्पाद केन्द्रों में विद्यमान हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरूआत उनके पूजन के बिना अधूरी मानी जाती है। उनके स्वरूप में ही गहन प्रतीकात्मकता निहित है, हाथी का विशाल मस्तक विवेक और दूरदर्शिता का प्रतीक है, छोटा मुख संयमित वाणी का द्योतक है, बड़े कान अधिक सुनने और कम बोलने की शिक्षा देते हैं, छोटा नेत्र गहराई से देखने की प्रेरणा देता है और विशाल उदर सहिष्णुता व समावेशिता का बोध कराता है। मनुष्य के दैनिक कार्यों में सफलता, सुख-समृद्धि की कामना, बुद्धि एवं ज्ञान के विकास एवं किसी भी मंगल कार्य को निर्विघ्न सम्पन्न करने हेतु गणेशजी को ही सर्वप्रथम पूजा जाता है, याद किया जाता है। प्रथम देव होने के साथ-साथ उनका व्यक्तित्व बहुआयामी है, लोकनायक का चरित्र हैं। गणेश शिवजी और पार्वती के पुत्र हैं, ऐसे सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं सार्वदैशिक लोकप्रियता वाले देव का जन्मोत्सव भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को सम्पूर्ण दुनिया में उमंग एवं हर्षोल्लास से मनाया जाता है। गणेशोत्सव हिन्दुओं का एक उत्सव है।

भारतीय धर्म-दर्शन में गणेश जी ह्यआरंभ के देवताह्न हैं। वैदिक परंपरा से लेकर पुराणों और लोककथाओं तक, वे हर युग में ह्यमार्गदर्शकह्न बने रहे हैं। यही कारण है कि उन्हें ह्यसवोर्पास्यह्न देवता कहा गया, सभी पंथों, संप्रदायों और वर्गों के लोग उनके पूजन में समान रूप से भाग लेते हैं। गणेशजी को प्रथम लिपिकार माना जाता है उन्होंने ही देवताओं की प्रार्थना पर वेद व्यासजी द्वारा रचित महाभारत को लिपिबद्ध किया था। जैन एवं बौद्ध धर्मों में भी गणेश पूजा का विधान है। अनंतकाल से अनेक नामों से गणेश दुख, भय, चिन्ता इत्यादि विघ्न के हरणकर्ता के रूप में पूजित होकर मानवों का संताप हरते रहे हैं। गणेश जी का पूजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का माध्यम भी है। स्वतंत्रता संग्राम के दौर में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप दिया। इससे गणेश चतुर्थी केवल पारिवारिक पर्व न रहकर जनजागरण और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बन गई। तिलक ने इसे सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय चेतना के मंच के रूप में स्थापित किया, जिसने भारत को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वर्तमान काल में स्वतंत्रता की रक्षा, राष्ट्रीय चेतना, भावनात्मक एकता और अखंडता की रक्षा के लिए गणेशजी की पूजा और गणेश चतुर्थी के पर्व का उत्साहपूर्वक मनाने का अपना विशेष महत्व है। आज के समय में जब समाज विभिन्न मत-मतांतरों, भाषाओं और संस्कृतियों में बंटा दिखाई देता है, तब गणेशजी पुनः राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बनकर सामने आते हैं। उनका स्वरूप हमें विविधता में एकता, सहिष्णुता, धैर्य और विवेकपूर्ण निर्णय की प्रेरणा देता है। गणेश जी हमें बताते हैं कि बुद्धि और करुणा का समन्वय ही प्रगति का मार्ग है। आज जब विश्व हिंसा, कट्टरता और असहिष्णुता से जूझ रहा है, तब गणेश चतुर्थी का पर्व हमें समन्वय और सहयोग का संदेश देता है। वे केवल धार्मिक आस्था के देवता ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय एकता के जीवंत प्रतीक हैं।

हिन्दुओं में गणेशजी के जन्म के विषय में अलग-अलग कथाएँ प्रचलित हैं। वराह पुराण के अनुसार स्वयं शिव ने पंच तत्त्वों को मिला कर गणेश का निर्माण बहुत तन्मयता से किया। जिससे वे अत्यंत सुन्दर और आकर्षक बने तो देवताओं में खलबली मच गयी, स्थिति को भांप कर शिव ने गणेश के पेट का आकार बढ़ा दिया और सिर को गजानन की आकृति का कर दिया ताकि उनके सौन्दर्य और आकर्षण को कम किया जा सके। शिव पुराण के अनुसार एक बार पार्वती ने अपने उबटन के मैल से एक पुतला बनाया और उसमें जीवन डाल दिया। इसके उपरांत उन्होंने इस जीवधारी पुतले को द्वार पर प्रहरी के रूप में बैठा दिया और उसे आदेश दिया कि वह किसी भी व्यक्ति को अंदर न आने दे। इसके बाद वे स्नान करने लग गई। संयोगवश कुछ ही समय बाद शिव उधर आ निकले। उनसे सर्वथा अपरिचित गणेश ने शिव को भी अंदर जाने से रोक दिया। इस पर शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का मस्तक काट दिया। पार्वती ने यह देखा तो वे बहुत दुखी हुईं। तब पार्वती को प्रसन्न करने के लिए शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर गणेश के धड़ से लगाकर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। तभी से गणेश, गजानन कहलाए। लेकिन बालक की आकृति से पार्वती बहुत दुखी हुई तो सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद और अतुलनीय उपहार भेंट किए, उन्हें प्रथम देव के रूप में सभी अधिकार प्रदत्त किये। इंद्र ने अंकुश, वरुण ने पाश, ब्रह्मा ने अमरत्व, लक्ष्मी ने ऋद्धि-सिद्धि और सरस्वती ने समस्त विद्याएँ प्रदान कर उन्हें देवताओं में सर्वोपरि बना दिया।

ऋद्धि-सिद्धि गणेशजी की पत्नियाँ हैं। वे प्रजापति विश्वकर्ता की पुत्रियां हैं। गणेश की पूजा यदि विधिवत की जाए, तो इनकी पतिव्रता पत्नियां ऋद्धि-सिद्धि भी प्रसन्न होकर घर-परिवार में सुख-शांति-समृद्धि और संतान को निर्मल विद्या-बुद्धि देती है। सिद्धि से ह्यक्षेमह्न और ऋद्धि से ह्यलाभह्न नाम के शोभा सम्पन्न दो पुत्र हुए। जहां भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं तो उनकी पत्नियां ऋद्धि-सिद्धि यशस्वी, वैभवशाली व प्रतिष्ठित बनाने वाली होती है। वहीं शुभ-लाभ हर सुख-सौभाग्य देने के साथ उसे स्थायी और सुरक्षित रखते हैं।

जन-जन के कल्याण, धर्म के सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप प्रदान करने एवं सुख-समृद्धि-निर्विघ्न शासन व्यवस्था स्थापित करने के कारण मानव-जाति सदा उनकी ऋणी रहेगी। आज के शासनकताओं को गणेश के पदचिन्हों पर चलने की जरूरत है। गणेशजी की सम्पूर्ण शारीरिक रचना के पीछे भगवान शिव की व्यापक सोच रही है। एक कुशल, न्यायप्रिय एवं सशक्त शासक एवं देव के समस्त गुण उनमें समाहित किये गये हैं। गणेशजी का गज मस्तक हैं अर्थात वह बुद्धि के देवता हैं। वे विवेकशील हैं। उनकी स्मरण शक्ति अत्यन्त कुशाग्र हैं। हाथी की भ्रांति उनकी प्रवृत्ति प्रेरणा का उद्गम स्थान धीर, गंभीर, शांत और स्थिर चेतना में है। हाथी की आंखें अपेक्षाकृत बहुत छोटी होती हैं और उन आँखों के भावों को समझ पाना बहुत कठिन होता है। दरअसल गणेश तत्ववेत्ता के आदर्श रूप हैं। गण के नेता में गुरुता और गंभीरता होनी चाहिए। उनके स्थूल शरीर में वह गुरुता निहित है। उनका विशाल शरीर सदैव सतर्क रहने तथा सभी परिस्थितियों एवं कठिनाइयों का सामना करने के लिए तत्पर रहने की भी प्रेरणा देता है। उनका लंबोदर दूसरों की बातों की गोपनीयता, बुराइयों, कमजोरियों को स्वयं में समाविष्ट कर लेने की शिक्षा देता है तथा सभी प्रकार की निंदा, आलोचना को अपने उदर में रख कर अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। छोटा मुख कम, तर्कपूर्ण तथा मृदुभाषी होने का द्योतक है।

गणेश का व्यक्तित्व रहस्यमय हैं, जिसे पढ़ पाना एवं समझ पाना हर किसी के लिये संभव नहीं है। शासक भी वही सफल होता है जिसके मनोभावों को पढ़ा और समझा न जा सके। इस प्रकार अच्छा शासक वही होता है जो दूसरों के मन को तो अच्छी तरह से पढ़ ले परन्तु उसके मन को कोई न समझ सके।

दरअसल वे शौर्य, साहस तथा नेतृत्व के भी प्रतीक हैं। उनके हेरांब रूप में युद्धप्रियता का, विनायक रूप में यक्षों जैसी विकरालता का और विघ्नेश्वर रूप में लोकरंजक एवं परोपकारी स्वरूप का दर्शन होता है।

गण का अर्थ है समूह। गणेश समूह के स्वामी हैं इसीलिए उन्हें गणाध्यक्ष, लोकनायक, गणपति आदि नामों से पुकारा जाता है। इसलिए गणेश चतुर्थी मनाना केवल धार्मिक परंपरा का निर्वाह नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने, सामाजिक समरसता को मजबूत करने और राष्ट्रीय एकता को पुष्ट करने का संकल्प है।

कोई हमसे सीखे

अमरीका, यानी कि महानता का वह परचम, जो जमीन पर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में फहरता है। उसका नाम सुनते ही लगता है कि बस अब ज्ञान की गंगा बहने वाली है, और हमारी तरह के साधारण प्राणियों का मोक्ष हो जाएगा। पर मोक्ष तो हुआ नहीं, उलटे गंगा ही प्रदूषण से भर गई। हमारे देश के नेता, जो किसी भी बाहरी देश में जाकर अपने आप को भगवान का अवतार मान लेते हैं, एक बार अमरीका के दौरे पर गए। उनके साथ था एक बड़ा-सा दल, जिसमें कुछ ऐसे बुद्धिजीवी थे जो भारतीय संस्कृति को सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए इस्तेमाल करते थे, और कुछ ऐसे चमचे जो हर चीज पर 'वाह-वाह' करने का ठेका लिए हुए थे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि अमरीका एक महान देश है, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ हर कोई महान है, यहाँ तक कि महान होने की मशीनें भी हैं। जैसे, अगर आपको एक महान फिल्म बनानी है, तो मशीन में कुछ डॉलर डालो और फिल्म बाहर आ जाएगी। अगर आपको महान संगीत बनाना है, तो एक और मशीन है। अगर आपको महान वैज्ञानिक बनना है, तो उसके लिए भी एक मशीन है। पर हमारे नेता तो ठहरे भारतीय, वे मशीनों में विश्वास नहीं करते। वे तो मनुष्य की मेहनत और लगन में विश्वास करते हैं। और इसी विश्वास के साथ उन्होंने एक ऐसा कार्य करने का निर्णय लिया, जिससे अमरीका की महानता पर प्रश्नचिह्न लग गया। हमारे नेता ने अमरीका के राष्ट्रपति से कहा, "मैं आपके देश की महानता को परखना चाहता हूँ। मुझे कोई महान काम करके दिखाइए।" राष्ट्रपति ने सोचा, ये भारत से आए हैं, शायद इन्हें कुछ मालूम नहीं। उन्होंने अपने सबसे महान वैज्ञानिकों को बुलाया और कहा, "इस आदमी को चाँद पर ले जाओ और वहाँ से धरती पर एक गिलास पानी लाओ।" पर हमारे नेता ने कहा, "यह तो साधारण काम है, इसमें महानता कहाँ? मैं तो इससे भी बड़ा काम करके दिखा सकता हूँ।" और उन्होंने अपने दल के सबसे आलसी, सबसे निकम्मे सदस्य को बुलाया और कहा, "जाओ, अमरीका के सबसे अमीर आदमी से जाकर कहो कि तुम्हें भीख चाहिए।"

यह सुनकर राष्ट्रपति और उनके वैज्ञानिक सन्न रह गए। "यह क्या? भीख? हमारे महान देश में भीख कहाँ?" पर हमारे नेता ने कहा, "यही तो असली महानता है। तुम्हारे पास सब कुछ है, पर तुम्हारे पास वो इंसान नहीं जो बिना मेहनत के कुछ भी मांग सके। और हमारे पास ऐसे लोगों की फौज है।" तो उस आलसी और निकम्मे इंसान ने अमरीका के सबसे अमीर आदमी को एक खत लिखा, "मैं आप से भीख मांगता हूँ। मुझे कुछ दीजिए, वर्ना मैं भूखा मर जाऊंगा।" अमीर आदमी ने सोचा, यह कोई नया रूं है। उसने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पर हमारे नेता ने कहा, "यही तो कमी है। तुम्हारी महानता यहीं पर खत्म हो जाती है। तुम्हारे यहाँ भीख मांगने वाला भी एक अपराधी है।" अगले दिन, हमारे नेता ने एक और काम किया। उन्होंने अपने दल के सबसे अयोग्य और बेकाबू सदस्य को बुलाया और कहा, "जाओ, यहाँ की सरकार में कोई पद मांगो।" राष्ट्रपति ने सोचा, यह तो और भी बड़ा मजाक है। हमारे यहाँ हर पद के लिए योग्यता की परीक्षा होती है। पर हमारे नेता ने कहा, "तुम्हारी योग्यता की परीक्षा तो तुम्हारे यहाँ के अयोग्य लोगों को देखती ही नहीं।" और उस अयोग्य आदमी ने राष्ट्रपति से कहा, "मुझे स्वास्थ्य मंत्री बना दो। मैं लोगों को खुद इलाज करना सिखाऊंगा।" यह सुनकर राष्ट्रपति ने उसे भगा दिया। पर हमारे नेता ने कहा, "यही तो तुम्हारी हार है। तुम उसे भगा सकते हो, पर हम उसे अपना नेता बना सकते हैं। और यही हमारी महानता है।" और फिर, सबसे बड़ी घटना हुई। हमारे नेता ने राष्ट्रपति से कहा, "मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली महानता क्या होती है।" उन्होंने अपने सबसे भ्रष्ट और लालची सदस्य को बुलाया और कहा, "जाओ, अमरीका के सबसे बड़े चर्च में जाकर कहो कि तुमने भगवान को खरीद लिया है।"

राष्ट्रपति का मुँह खुला का खुला रह गया। "तुम मजाक कर रहे हो।" पर हमारे नेता ने कहा, "यही तो महानता है। तुम सोचते हो कि भगवान को खरीदा नहीं जा सकता, पर हमारे यहाँ तो नेता, भगवान और धर्म सब एक ही बाजार में बिकते हैं।" तो वह लालची आदमी चर्च गया और पुजारी से कहा, "मैंने भगवान को खरीद लिया है।" पुजारी ने उसे पागल समझकर भगा दिया

। पर हमारे नेता ने कहा, "यही तो तुम्हारा दुख है। तुम धर्म को व्यापार नहीं बनाते। और हमारे यहाँ तो धर्म ही सबसे बड़ा व्यापार है।"

हमारे नेता ने अमरीका को एक ऐसा सवाल दिया, जिसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा, "तुम्हारे पास इतनी महानता है, इतना ज्ञान है, इतना पैसा है... पर फिर भी तुम दुखी क्यों हो?" राष्ट्रपति ने कहा, "हम दुखी नहीं हैं। हम तो खुश हैं।" पर हमारे नेता ने मुस्कुराते हुए कहा, "नहीं, तुम दुखी हो। तुम हर दिन यही साबित करने में लगे रहते हो कि तुम महान हो। और यही महानता तुम्हें दुख देती है।" और फिर हमारे नेता अपने देश वापस आ गए। उनके पीछे अमरीका की जनता खड़ी थी, और उनकी आँखों में आँसू थे। वे रो रहे थे, पर उनका दुख हमारी तरह का नहीं था। उनका दुख महानता का दुख था, जो कभी खत्म नहीं होता। और यही अमरीका की सबसे बड़ी विडंबना थी, जिसे हमारे नेता ने बेनकाब कर दिया था।

संसद के हंगामे से लोकतंत्र का मजाक बन रहा है

राजेश कुमार पासी

लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक मंदिर की तरह होती है क्योंकि उसमें जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं । देखा जाए तो एक तरह से जनता ही संसद में बैठती है और वहां से शासन चलाती है । मंदिर पूजा-अर्चना करने की जगह होती है. अगर पूजा सड़कों पर होने लगे तो मंदिर की जरूरत पर सवाल खड़ा हो जाएगा । कुछ ऐसा ही हमारे देश में संसद के साथ हो रहा है । सड़कों पर सरकार से सवाल पूछा जा रहा है और संसद में हंगामा किया जा रहा है । संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष सरकार से सवाल संसद में करता है और अगर वो उसका जवाब न दे तो सड़कों पर उतर पर उससे जवाब मांगता है । समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि सड़के अगर खामोश रहेंगी तो संसद आवारा हो जाएगी । इसका मतलब है कि जनता को लोकतंत्र जिंदा रखने के लिए जागना पड़ता है । सवाल यह है कि जब सब कुछ सड़कों पर ही होना शुरू हो जाए ,तब संसद खामोश हो जाएगी । आज हमारे देश में कुछ ऐसा ही हो रहा है । संसद सिर्फ हंगामा करने के लिए रह गई है । पिछले कई सालों से देखने में आ रहा है कि संसद में कामकाज बंद हो गया है, सिर्फ हंगामा हो रहा है । इस बार संसद में 120 घंटे काम करने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन लोकसभा में सिर्फ 37 घंटे ही काम हुआ जबकि दूसरी तरफ राज्यसभा में 120 घंटे की जगह सिर्फ 47 घंटे काम हुआ है । इस तरह देखा जाए तो लोकसभा ने 120 में से 83 घंटे बर्बाद कर दिए तो दूसरी तरफ राज्यसभा ने 73 घंटे बर्बाद किए । इस तरह संसद ने अपने कामकाज के 156 घंटे बर्बाद किये ।

सपा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की कुर्सी एक ही परिवार में क्यों

संजय सक्सेना

समाजवादी पार्टी में इस समय पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक (पीडीए) को लेकर काफी गंभीर मतभेद नजर आ रहे हैं। ऐसा इस लिये हैं क्योंकि पीडीए की बात करने वाले सपा प्रमुख अखिलेश ने पार्टी के सभी प्रमुख पदों पर अपने परिवार के लोगों को बैठा रखा है। चुनाव के समय टिकट बांटते समय भी सपा आलाकमान सबसे पहले अपने और परिवार के बारे में ही सोचता है। यही वजह है मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पहले मुलायम सिंह का कॉपीराइट हुआ करता था और उनके बाद उनके पुत्र अखिलेश यादव ने इन दोनों पदों को अपनी जागीर बना रखा है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी नेता के पद पर भी अखिलेश यादव काबिज हैं। मुलायम कुनबे के पांच सदस्य सांसद हैं। समाजवादी पार्टी में मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष का पद एक ही परिवार तक सीमित रहता है। दो बार मुलायम सिंह और एक बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा कोई दूसरा सीएम नहीं बना। इससे आगे की बात की जाये तो मुख्यमंत्री होते हुए भी यह दोनों नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर भी विराजमान रहे। मुलायम कुनबे ने इन तीन पदों पर ना तो अपने से इतर कभी किसी पिछड़े समाज के नेता को आगे बढ़ाया ना ही दलित या फिर अल्पसख्यक नेता को इन पदों के लिये मौका मिला। ऐसे में अखिलेश का पीडीए छलावा ही नजर आता है। यही बात आज पार्टी से बाहर निकाली गई विधायक पूजा पाल कह रही हैं और इससे पहले भी कई नेता कह चुके हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या पीडीए के अन्य नेता सीएम या पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के लायक नहीं हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि क्या समाजवादी एक परिवार तक सीमित होकर रह गई है। क्या पीडीए के नाम पर अखिलेश यादव अन्य जातियों को धोखा दे रहे हैं?

गौरतलब हो, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनावों के बाद से पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) को अपनी मुख्य रणनीति बनाया। अखिलेश ने इसे एक सामाजिक गठजोड़ के रूप में पेश किया, जहां पिछड़े वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक एकजुट होकर भाजपा को चुनौती देंगे। 2024 लोकसभा चुनावों में सपा की 37 सीटों की जीत को पीडीए की सफलता बताया गया। लेकिन पार्टी के भीतर उभरती कलह और कई नेताओं के बयान बताते हैं कि यह रणनीति महज एक चुनावी जुमला है, जिसके नाम पर अखिलेश अन्य बिरादरियों के नेताओं को धोखा दे रहे हैं। पीडीए में पी और डी को दरकिनार कर सिर्फ ए (अल्पसंख्यक, मुख्यतः मुस्लिम) पर फोकस करने के आरोप लग रहे हैं, जो पार्टी छोड़ने वाले नेताओं के बयानों से पुष्ट होते हैं। यह स्टोरी इन आरोपों की पड़ताल करती है, जहां कलह की जड़ परिवारवाद, जातिवाद और अल्पसंख्यक तुष्टिकरण में छिपी है।

पार्टी के भीतर कलह की शुरूआत 2023-24 से ही दिखने लगी, जब पीडीए की घोषणा के बाद कई प्रमुख नेता से अलग हुए। सबसे बड़ा नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का है, जो पिछड़े वर्ग (कुर्मी) से आते हैं। मौर्य ने फरवरी 2024 में सपा छोड़कर अपनी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाई। उनके बयान में साफ कहा गया कि अखिलेश पीडीए के नाम पर पिछड़ों और दलितों को ठग रहे हैं। पार्टी में सिर्फ यादव और मुस्लिमों का बोलबाला है, अन्य जातियों को टिकट या पद नहीं मिलते। मौर्य ने आरोप लगाया कि सपा में परिवारवाद हावी है, जहां अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव और अन्य रिश्तेदारों को तरजीह दी जाती है, जबकि के अन्य घटक सिर्फ वोट बैंक हैं। मौर्य के जाने के बाद सपा में हलचल मची, लेकिन अखिलेश ने इसे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा करार दिया।

पिछड़े वर्ग से ही ओम प्रकाश राजभर ने भी सपा पर हमला बोला। राजभर, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख हैं, 2023 में सपा से अलग होकर एनडीए में शामिल हो गये थे। अगस्त 2025 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजभर ने कहा, अखिलेश पीडीए की बात करते हैं, लेकिन असल में उन्हें धोखा देते हैं।सपा नेता गायत्री प्रजापति, रामकांत यादव जेल में हैं, लेकिन अखिलेश सिर्फ एक जाति को बढ़ावा देते हैं। वे सभी जातियों से वोट लेते हैं, लेकिन इस्तेमाल करते हैं। राजभर ने पीडीए को फर्जी बताया और कहा कि अखिलेश ने कुम्हार समुदाय जैसे छोटे पिछड़ों को कभी महत्व नहीं दिया। राजभर के बयान से सपा में पिछड़ों की नाराजगी उजागर हुई, जो 2025 बाय-इलेक्शन में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है।समाजवादी पार्टी में दलित बिरादरी भी असंतोष स्थिति में है। अवधेश प्रसाद, जो समाजवादी पार्टी के आयोध्या से सांसद हैं, के करीबी मोईद खान पर 2024 में एक नाबालिग दलित लड़की से बलात्कार का आरोप लगा।

इस घटना ने पीडीए की साख पर सवाल उठाए। दलित नेता और पूर्व समाजवादी सदस्य रामजी लाल सुमन ने कहा कि अखिलेश ने 2012 में 2.5 लाख दलितों को डिमोट किया और 3 लाख बहुजन छात्रों की स्कॉलरशिप रोकी। सपा में दलितों के लिए कुछ नहीं, सिर्फ नाम।सुमन ने राजपूत शासक राणा संगा को गद्दार कहने पर भी अखिलेश की आलोचना की, जो दलित-राजपूत गठजोड़ को तोड़ता है। हाल ही में विधायक पूजा पाल को पार्टी से निकाला गया। पाल ने आरोप लगाया कि अखिलेश परिवारवाद चला रहे हैं, पीडीए सिर्फ दिखावा है। करहल में दलितों पर हमले और सीतापुर में दलित घरों को जलाने की घटनाएं समाजवादी पार्टी शासनकाल की याद दिलाती हैं, जहां दलित अपराध राष्ट्रीय औसत से 5 गुना ज्यादा थे।अल्पसंख्यकों को छलने का आरोप सबसे गंभीर है। अखिलेश अपने परिवर के अलावा सिर्फ मुस्लिम नेताओं को प्राथमिकता देते हैं।

पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर जलमग्न, गुरुद्वारा दरबार साहिब बाढ़ से घिरा, 300 लोग फंसे

एजेंसी

नारोवाल (पंजाब)। पाकिस्तान में रावी नदी के उफान पर आने से पंजाब प्रांत का नारोवाल जिला बाढ़ से घिर गया है। करतारपुर कॉरिडोर के जलमग्न हो जाने से बुधवार सुबह लगभग 300 लोग फंस गए। करतारपुर गुरुद्वारा दरबार साहिब तो पूरी तरह जलमग्न हो गया है। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सेना को बुलाया गया। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार, सेना को पंजाब प्रांत के बाढ़ प्रभावित छह जिलों में तैनात किया गया है। बाढ़ प्रभावित जिलों में नारोवाल प्रमुख है। रावी नदी का पानी गुरुद्वारा दरबार साहिब तक पहुंच गया है। इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि बाढ़ का पानी गुरुद्वारा साहिब परिसर में घुस गया है। परिसर के कुछ हिस्सों में पानी का स्तर लगभग तीन फीट तक पहुंच गया है। बाढ़ के कारण गुरुद्वारा प्रांगण और मुख्य सीढ़ियां डूब गई हैं। तीर्थयात्री वहीं फंसे हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल निकासी और सफाई कार्य पूरा होने के बाद ही गुरुद्वारा साहिब के दर्शन शुरू हो पाएंगे। पंजाब के अधिकारियों के अनुसार, लाहौर, फैसलाबाद, ओकारा, कसूर, सियालकोट और नरोवाल जिले में बचाव और राहत कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। सतलुज नदी के किनारे कसूर और गंदा सिंह वाला सहित कई इलाके जलमग्न हो गए हैं।

बांग्लादेश में पुलिस का प्रदर्शनकारी इंजीनियरिंग छात्रों पर लाठीचार्ज, कम से कम 10 घायल

ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आज दोपहर देशभर के इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों के प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने बलपूर्वक मुख्य सलाहकार के आवास राज्य अतिथिगृह यमुना की तरफ बढ़ने से रोक दिया। पुलिस ने इसके लिए आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार की। आखिर में लाठीचार्च कर उन्हें तितर-बितर करने की कोशिश की। पुलिस लाठीचार्च में कम से कम 10 व्यक्ति घायल हो गए। द डेली स्टार और ढाका ट्रिब्यून अखबार की खबर के अनुसार इस प्रदर्शन में बांग्लादेश इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (बीयूईटी) और अन्य इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी शामिल हुए। छात्रों ने आज सुबह अपनी तीन सूत्री मांगों को लेकर ढाका में शाहबाग चौराहे को जाम लगा दिया। यहां से छात्र दोपहर करीब एक बजे राज्य अतिथिगृह यमुना की ओर बढ़े। पुलिस ने दोपहर करीब डेढ़ बजे बैरिकेड लगाकर जुलूस को इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के पास रोक लिया। पुलिस के अनुसार छात्रों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, इसलिए उन्हें तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया गया। इसके बाद छात्र होटल के सामने बैठ गए, तो पुलिस ने पानी की बौछार शुरू कर दी।

पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश का कहर, अब तक 802 लोगों की मौत, 1,000 से अधिक घायल

इस्लामाबाद । राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 26 जून से अब तक पाकिस्तान में लगातार मानसूनी बारिश और बाढ़ के कारण कम से कम 802 लोगों की जान चली गई है। वहीं, 1,088 अन्य घायल हो गए हैं। खराब मौसम ने बड़े स्तर पर तबाही मचाई है। घरों में पानी भर गया है, जिससे हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है और पूरे देश में आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रयासों पर दबाव पड़ा है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जहां सबसे अधिक 479 लोगों की मौत हुई है। यहां पर 347 लोग घायल हुए हैं। वहीं, पंजाब में 165 लोग मारे गए और 584 घायल हुए, इसके बाद सिंध में 57 लोग मारे गए और 75 घायल हुए, जबकि बलूचिस्तान में 24 लोगों की मौत हुई और 5 लोग घायल हुए। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान में 45 लोग मारे गए या घायल हुए, जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 24 लोगों की मौत हुई और 29 लोग घायल हुए। इसके अलावा, इस्लामाबाद में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 8 लोगों की मौत हुई और 3 घायल हुए।

श्रीलंका में स्कूल वैन दुर्घटना में दो छात्रों की मौत, 13 घायल

कोलंबो। श्रीलंका के उत्तर-पश्चिमी प्रांत के कुलियापिटिया में एक स्कूल वैन और एक टिपर ट्रक की टक्कर में दो स्कूली छात्रों समेत तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दुर्घटना में घायल हुए 13 अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में वैन का चालक भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि मामले की जाँच जारी है। गौरतलब है कि श्रीलंका में लापरवाही से वाहन चलाने की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हो रही है और वर्ष 2024 में 2,541 लोगों की मौत हो गयी थी।

इजराइली हमले में हमास के तकनीकी विशेषज्ञ महमूद अल-असवाद को मारे जाने का दावा

एजेंसी

गाजा पट्टी। इजराइली सेना ने गाजा में ताजा हमले में आतंकवादी समूह हमास का तकनीकी विशेषज्ञ महमूद अल-असवाद के मारे जाने का दावा किया है। इस हमले में पांच अन्य लोगों के भी मारे जाने की खबर है। इनमें गाजा पट्टी में रहने वाले अंतरराष्ट्रीय एथलीट आलम अब्दुल्ला अल-अमौर और चार फिलिस्तीनी नागरिक शामिल हैं। इससे पहले इजराइल के एक अन्य हमले में गाजा के प्रसिद्ध पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी सुलेमान अल-ओबेद की भी जान चुकी है। इजराइल रक्षा बल (आईडीएफ) के एक्स हैंडल, फिलिस्तीन की समाचार एजेंसी वफा, अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबरों में यह जानकारी दी गई है। आईडीएफ के अनुसार, मारा गया महमूद अल-असवाद पश्चिमी गाजा क्षेत्र में हमास के सामान्य सुरक्षा तंत्र की कमान संभालता था। वह हमास का तकनीकी विशेषज्ञ था।

इसके अलावा दक्षिणी गाजा पट्टी में खान यूनिस के दक्षिण-पश्चिम में अल-टीना सहायता केंद्र के पास इजराइली सेना की गोलीबारी में सहायता की प्रतीक्षा कर रहे चार फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए और कुछ अन्य घायल हो गए। इजराइली तोपखाने से उत्तर में जबालिया अल-नजला के दक्षिणी इलाकों में आवासीय इमारतों पर गोलाबारी जारी है। इजराइली लड़ाकू विमानों ने मध्य गाजा पट्टी में अल-नुसेरात शरणार्थी शिविर के पश्चिम में अल-सवाराह क्षेत्र में कृषि भूमि पर दो हवाई हमले किए। खान यूनिस में गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के सहायता वितरण केंद्र के पास आईडीएफ की गोलीबारी में गाजा के एथलीट आलम अब्दुल्ला अल-अमौर की जान चली गई। इस पर इजराइली रक्षा बलों ने तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। तीन हफ्ते पहले ऐसे ही एक हमले में गाजा के प्रसिद्ध पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी सुलेमान अल-ओबेद की जान चली गई थी।

मिनियापोलिस के कैथोलिक स्कूल में गोलीबारी, 3 की मौत, 20 घायल

एजेंसी

मिनियापोलिस। अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में एक कैथोलिक स्कूल में हुई भीषण गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि हमलावर भी मारे गए लोगों में शामिल हैं। यह घटना एनुंसिएशन कैथोलिक स्कूल (nnunciation Catholic School) में हुई, जो लगभग 395 छात्रों वाला एक निजी प्राथमिक विद्यालय है। गोलीबारी उस समय शुरू हुई जब छात्र सुबह की प्रार्थना में शामिल थे। स्थानीय मीडिया ने बताया कि हमलावर काले कपड़ों में और राइफल से लैस था। मिनियापोलिस पुलिस ने बताया कि स्थिति काबू में है और अब कोई सक्रिय खतरा नहीं है। एफबीआई और होमलैंड सिक्योरिटी मौके पर मौजूद हैं। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज़ ने घटना को 'भयानक हिंसक कृत्य' बताया।

राष्ट्रपति ट्रंप ने दी प्रतिक्रिया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि 'मैं इस दुखद घटना पर पूरी तरह से अवगत हूं। एफबीआई ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और वे घटनास्थल पर हैं। व्हाइट हाउस इस भयावह स्थिति पर नजर रखेगा। कृपया मेरे साथ मिलकर इसमें शामिल सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि एनुंसिएशन कैथोलिक स्कूल में गोलीबारी हुई। मिनियापोलिस शहर के अधिकारियों के अनुसार, हमलावर को नियंत्रित कर लिया गया है और निवासियों के लिए कोई सक्रिय खतरा नहीं है।

मोल्दोवा की राष्ट्रपति का संदेश- 'मोल्दोवा का फैसला सिर्फ मोल्दोवावासी करेंगे'

एजेंसी

किशिनाउ। मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने देश की स्वतंत्रता की 34वीं वर्षगांठ पर एक महत्वपूर्ण संदेश देते हुए कहा कि मोल्दोवा का भविष्य सिर्फ मोल्दोवावासी तय करेंगे। यह बयान उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की मौजूदगी में दिया। इन तीनों यूरोपीय नेताओं ने मोल्दोवा के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेकर देश के यूरोपीय संघ में शामिल होने के प्रयासों के प्रति समर्थन जताया। राष्ट्रपति सांडू ने कहा, यूरोपीय संघ (ईयू) में शामिल होना कोई दूर का सपना नहीं बल्कि एक प्रोजेक्ट है जिस पर हम काम कर रहे हैं। बिना ईयू के मोल्दोवा अतीत में फंसा रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यूरोप और मोल्दोवा के बीच फिर कभी दूरी नहीं आनी चाहिए। सांडू ने अपने भाषण में रूस की कथित गतिविधियों का भी जिक्र किया, जिनमें चुनावों में हस्तक्षेप, दुष्प्रचार अभियान, विदेशी फंडिंग से विरोध प्रदर्शन और अन्य प्रयास शामिल हैं, जिनका उद्देश्य मोल्दोवा की ईयू सदस्यता की राह में बाधा डालना है। चुनाव से पहले सांडू ने मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा, हमारा भविष्य सुरक्षित तभी होगा जब हम उसकी रक्षा करेंगे। मोल्दोवा का फैसला सिर्फ मोल्दोवावासी करेंगे। यह बयान ऐसे समय आया है जब देश में महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं, जो यह तय करेंगे कि मोल्दोवा यूरोप की राह पर आगे बढ़ता है या नहीं।

नेपाल में फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया एप को सात दिनों का अल्टीमेटम

एजेंसी

काठमांडू। नेपाल सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को निर्देश दिया है कि वे सात दिनों के भीतर देश में रजिस्टर्ड करें अन्यथा उनकी सेवाएं रोक दी जाएगी। सरकार की तरफ से फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप आदि सोशल मीडिया साइट्स को नेपाल में पंजीकरण के लिए बार-बार आग्रह करने के बाद भी यहां रजिस्टर्ड नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इन सोशल मीडिया साइट्स को अंतिम बार सात दिनों का समय देने का फैसला किया गया। कैबिनेट के इस निर्णय के बारे में सरकार के प्रवक्ता और संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने बताया कि बार बार आग्रह करने के बाद भी इसकी अनदेखी करने के कारण सरकार को कड़े कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को निर्धारित समय के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन का काम पूरा करना होगा। गुरूंग ने बताया कि अनुपालन में विफल रहने वाले प्लेटफार्मों को नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण द्वारा देश के भीतर निष्क्रिय करने का निर्देश दिया जाएगा। सोशल मीडिया प्रबंधन दिशा-निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जारी किए गए निर्देश में सभी सोशल मीडिया ऑपरेटरों को जवाबदेह और जिम्मेदार होने की बात कही गई है। प्लेटफ़ॉर्म के पास संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सार्वजनिक रूप से रजिस्ट्रेशन करने के लिए सात दिन हैं। सूचना मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरूंग ने कहा कि यह आखिरी मौका दिया गया है यदि इन सात दिनों के भीतर जिन सोशल मीडिया एप ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उसके बाद वह नेपाल में निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

ओली सरकार के संसद में विश्वास मत नहीं लिए जाने संबंधी रिट पर कोर्ट ने सभी दस्तावेज मंगवाए

एजेंसी

काठमांडू। सरकार को समर्थन दे रहे और सरकार में सहभागी एक दल के द्वारा प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद संवैधानिक प्रावधानों के तहत 30 दिन के भीतर संसद में विश्वास का मत नहीं लेने संबंधी एक रिट पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित सभी दस्तावेज जमा करने का आदेश दिया है।

सरकार में सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के द्वारा ओली सरकार को दिए जा रहे समर्थन को वापस लेने के बाद 30 दिन के भीतर प्रधानमंत्री द्वारा संसद में विश्वास का मत नहीं लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की गई थी। हालांकि 45 दिन के बाद इस पार्टी के तरफ से स्पीकर देवराज घिमिरे को समर्थन जारी रखने का पत्र दुबारा दिया गया। लेकिन नेपाल के संविधान में इस अवस्था में 30 दिन के भीतर ही प्रतिनिधि सभा में विश्वास का मत लेने का अनिवार्य प्रावधान है। इस रिट याचिका के संबंध में दस्तावेज जमा करने का आदेश देते हुए कोर्ट ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के द्वारा समर्थन वापस लेने, उनके मंत्री द्वारा इस्तीफा देने और दुबारा समर्थन देने संबंधी सभी दस्तावेज कोर्ट में जमा करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वीरेंद्र केसी द्वारा दायर रिट याचिका पर यह दूसरी सुनवाई थी। न्यायमूर्ति महेश शर्मा पौडेल और न्यायमूर्ति नृपद्वाज निरौला की पीठ ने संसद सचिवालय को निर्देश दिया कि वह नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के द्वारा स्पीकर को सौंप गए सभी पत्र जमा करने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया है कि वह नागरिक उनमुक्ति पार्टी के भीतर वैधता और नेतृत्व विवाद के बारे में जो भी विवरण है उसे कोर्ट के जमा करे। याचिकाकर्ता का दावा है कि ओली सरकार से समर्थन वापस लेने का निर्णय पार्टी की संसदीय दल की बैठक से किया गया है जबकि दुबारा समर्थन देने का पत्र पार्टी की अध्यक्ष रंजीता श्रेष्ठ के तरफ से बिना पार्टी की बैठक के ही दिया गया है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सरकार में नागरिक उन्मुक्ति पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री अरुण कुमार चौधरी का आधिकारिक इस्तीफा पत्र प्रस्तुत किया जाए। सरकार से समर्थन वापसी के साथ ही चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री के तरफ से उसे स्वीकृत नहीं किया गया है।

अमेरिकी अदालत ने किल्मार अब्रेगो गार्सिया के निर्वासन पर लगाई रोक, 6 अक्टूबर को होगी सुनवाई

एजेंसी

वॉशिंगटन। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने किल्मार अब्रेगो गार्सिया को देश से फिलहाल निर्वासित करने पर रोक लगा दी है। मैरीलैंड की जिला न्यायाधीश पाउला जिनिस ने आदेश जारी करते हुए कहा कि गार्सिया को 06 अक्टूबर को निर्धारित सुनवाई तक देश से बाहर नहीं भेजा जा सकता।

गार्सिया को वर्तमान में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (आईसीई) के एक डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। उनकी कानूनी टीम का कहना है कि गार्सिया अमेरिका में शरण लेना चाहते हैं, क्योंकि यदि उन्हें युगांडा भेजा गया तो वहां उन्हें यातना और उत्पीड़न का खतरा है। 30 वर्षीय एल सल्वाडोर के नागरिक गार्सिया को हाल ही में टेनेसी की एक जेल से रिहा होने के बाद बाल्टीमोर में गिरफ्तार किया गया था। प्रशासन का दावा है कि गार्सिया कुख्यात एमएस-13 गैंग से जुड़ा हुआ है, हालांकि गार्सिया ने इन आरोपों को खारिज किया है।गार्सिया ने इमिग्रेशन अधिकारियों से यह भी कहा है कि अगर उसे अमेरिका से बाहर भेजना ही पड़ा, तो वह कोस्टा रिका जाना पसंद करेगा।

प्रधानमंत्री ओली के पांच दिवसीय चीन भ्रमण की आधिकारिक घोषणा, मोदी और जिनपिंग से होगी मुलाकात

एजेंसी

काठमांडू। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर 30 अगस्त को पांच दिवसीय आधिकारिक यात्रा के लिए चीन रवाना होने वाले हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इसकी औपचारिक घोषणा की। चौथी बार सत्ता संभालने के बाद यह उनकी दूसरी चीन यात्रा है।

विदेश मंत्रालय के तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इस यात्रा में तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन 2025 में उनकी भागीदारी के साथ-साथ बीजिंग में जापान के आक्रमण के खिलाफ चीनी पीपुल्स वॉर ऑफ रेसिस्टेंस की विजय की 80वीं वर्षगांठ और विश्व फासीवादी विरोधी युद्ध के अवसर पर स्मारक कार्यक्रम शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस भ्रमण के

दौरान उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ उनकी साइडलाइन मुलाकात तय है। जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात बीजिंग में होगी जबकि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो तियांजिंग में ही मिलने वाले हैं।

विदेश मंत्रालय के बयान में यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री ओली तियांजिंग में आयोजित एससीओ प्लस के शिखर सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। शिखर सम्मेलन से इतर, नेपाली प्रधानमंत्री बीजिंग में आयोजित कार्यक्रम में सहभागी होने वाले हैं जिसमें कई विश्व नेताओं के साथ बैठकें भी करेंगे। बीजिंग में ओली 02 सितंबर को चीनी उपराष्ट्रपति हान झेंग से मिलने वाले हैं। अगले दिन, वह चीनी सरकार द्वारा आयोजित आधिकारिक वर्षगांठ कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री के प्रतिनिधिमंडल में शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री रघुजी पंत, संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री प्रसाद पांडे, संसद सदस्य पूर्ण बहादुर खडका, प्रधानमंत्री के आर्थिक और विकास सलाहकार डॉ. युवराज खतिवडा, संसद सदस्य छविलाल विश्वकर्मा के साथ वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। एस सी ओ में नेपाल डायलग पार्टनर के रूप में सहभागी होने जा रहा है। इस क्षेत्रीय संगठन में नेपाल सहित 14 देश हैं जबकि भारत चीन, रुस, पाकिस्तान सहित 10 देश हैं जबकि अफगानिस्तान और मंगोलिया इसमें पर्यवेक्षक देश के रूप में सहभागी होने वाले हैं। ओली और उनकी टीम को यात्रा समाप्त करने के बाद 3 सितंबर को वापस लौटना है।

रूस में व्लादिमीर के मेयर दिमित्री नौमोव धोखाधड़ी के संदेह में गिरफ्तार

एजेंसी

मॉस्को (रूस)। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने मध्य रूस के व्लादिमीर शहर के मेयर दिमित्री नौमोव को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी धोखाधड़ी के संदेह और अन्य आरोपों में की गई है। हालांकि नौमोव की गिरफ्तारी या उनके खिलाफ किसी भी आरोप की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। द मॉस्को टाइम्स अखबार की खबर में क्रेमलिन समर्थक अखबार आर्गुमेंटी आई फैक्टरी के हवाले से कहा गया कि संघीय सुरक्षा सेवा के एजेंटों ने मेयर दिमित्री नौमोव के कार्यालय का दरवाजा खुलने का इंतजार किया। कुछ देर इंतजार करने के बाद दरवाजा तोड़ दिया गया। एक कानून प्रवर्तन सूत्र ने बाद में सरकारी समाचार एजेंसी तास को बताया कि सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी के सदस्य दिमित्री नौमोव पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का संदेह है। सूत्र ने इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं दी।

इस बीच, स्थानीय प्रसारक जेबरा टीवी ने संकेत दिया कि नौमोव की गिरफ्तारी का संबंध एक कथित संगठित अपराध समूह से हो सकता है। इस समूह को कब्रिस्तान माफिया कहा जाता है। बताया गया है कि इसी साल मई में मेयर नौमोव ने अंतिम संस्कार सेवाओं से संबंद्ध दो कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। इसके

बाद व्लादिमीर क्षेत्र में अंतिम संस्कार का शुल्क बढ़ाने के संदेह में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल नौमोव की गिरफ्तारी या उनके खिलाफ किसी भी आरोप की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उनकी गिरफ्तारी व्लादिमीर में नगर परिषद चुनाव से तीन हफ्ते से भी कम समय पहले की गई है। नौमोव को नवंबर, 2022 में मेयर नियुक्त किया गया था।

ईरान ने यहूदी विरोधी हमलों पर ऑस्ट्रेलिया के आरोपों को खारिज किया

तेहरान। ईरान के विदेश मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया के उन आरोपों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि देश में हुए दो यहूदी विरोधी हमलों के पीछे उसका हाथ है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने यहां एक साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ के उन दावों का खंडन किया कि पिछले अक्टूबर में सिडनी में एक कोशर कैफ़े में आग लगने और पिछले दिसंबर में मेलबर्न में एक यहूदी प्रार्थनास्थल पर हुई बड़ी आगजनी के पीछे ईरान का हाथ था। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा ईरानी राजदूत अहमद सादेघी को निष्कासित करने के फैसले पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की करते हुए कहा ÷ यह एक नया घटनाक्रम है। मेरे सहयोगी इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं ताकि ईरान की प्रतिक्रिया पर निर्णय लिया जा सके। प्रवक्ता ने कहा कि पिछले दो हफ्तों में, हमने क़ब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों में लोगों की हत्या के विरोध में ऑस्ट्रेलिया में लाखों लोगों के प्रदर्शन देखे हैं,। ऑस्ट्रेलिया के कुछ राजनेताओं ने भी एक दुर्लभ कदम उठाते हुए इज़राइल की कार्रवाइयों की हल्की-फुल्की आलोचना की है। अल्बानीज़ ने घोषणा की थी कि ऑस्ट्रेलिया ने ईरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है और तेहरान स्थित अपने दूतावास का संचालन अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है।

एचडी हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज और एचडी हुंडई मिपो का जहाज निर्माण कंपनी एचडी केएसओई में हुआ विलय

एजेंसी

सियोल (दक्षिण कोरिया)। एचडी हुंडई के जहाज निर्माण व्यवसाय की देखरेख करने वाली मध्यवर्ती होल्डिंग कंपनी एचडी कोरिया शिपबिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग (एचडी केएसओई) ने एचडी हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज (एचएचआई) और एचडी हुंडई मिपो के विलय की योजना की घोषणा की। यह कदम अमेरिका के साथ बढ़ते जहाज निर्माण सहयोग के बीच प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने के लिए उठाया गया है। उलसान स्थित दो जहाज निर्माण सहायक कंपनियों का विलय पूरा होने के बाद एकीकृत इकाई एचडी एचएचआई के रूप में काम करेगी। द कोरिया टाइम्स अखबार की खबर के अनुसार, चीन और जापान में प्रमुख जहाज निर्माण कंपनियों के हालिया विलय का हवाला देते हुए एचडी केएसओई ने कहा कि यह एकीकरण विशेष रूप से नौसैनिक पोत बाजार में कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा। एचडी एचएचआई के विपरीत, जिसका युद्धपोतों के निर्माण और निर्यात में एक अच्छा रिकॉर्ड है, एचडी हुंडई मिपो के पास नौसैनिक जहाजों के निर्माण का लाइसेंस नहीं है, हालांकि, उसके पास युद्धपोत निर्माण के लिए उपयुक्त सुविधाएं मौजूद हैं। ब्रिटिश रक्षा उद्योग की पत्रिका जेन्स के अनुसार अगले 10 वर्षों में दुनिया भर में नौसैनिक जहाजों के लिए कुल 2,100 नए अनुबंध होने की उम्मीद है, जिनका कुल मूल्य 360 अरब डॉलर होगा। एचडी केएसओई ने कहा कि

एकीकृत एचडी एचएचआई का लक्ष्य 2035 तक रक्षा क्षेत्र से 10 ट्रिलियन वॉन (7.1 अरब डॉलर) का वार्षिक राजस्व उत्पन्न करना है। आर्कटिक शिपिंग मार्गों की बढ़ती मांग को देखते हुए, नई इकाई आइसब्रेकर सहित विशेष-उद्देश्य वाले जहाजों के बाजार में अपनी हिस्सेदारी का विस्तार करना चाहती है। एचडी केएसओई के एक अधिकारी ने कहा, विलय के साथ हम अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाएंगे और उन्नत तकनीकें हासिल करेंगे। विलय योजना के अतिरिक्त एचडी केएसओई ने एक निवेश फर्म की स्थापना की योजना की घोषणा की, जो वियतनाम और फिलीपींस सहित एचडी हुंडई के विदेशी परिचालनों की देखरेख के लिए जिम्मेदार होगी। यह नई कंपनी दिसंबर में सिंगापुर में स्थापित की जाएगी, ताकि थोक जहाज और टैंकर बाजारों में चीनी प्रतिस्पर्धियों से चुनौतियों का समाधान किया जा सके और विदेशी व्यापार के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके।

पंजाब नेशनल बैंक ने नई दिल्ली में पहली स्टार्टअप शाखा खोली, एसटीपीआई से समझौता

एजेंसी

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने नई दिल्ली में अपनी पहली स्टार्टअप-केंद्रित शाखा खोली है। इस शाखा का उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना और बैंकिंग समाधान के सभी पहलुओं सहित सेवाओं के माध्यम से नवाचार का समर्थन करना है। इसके अलावा पात्र स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता देने के लिए पीएनबी और एसटीपीआई के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।इस शाखा का उद्घाटन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) के महानिदेशक अरविंद कुमार और पीएनबी के एमडी एवं सीईओ अशोक चंद्रा की उपस्थिति में किया गया। इसके अलावा पीएनबी के महाप्रबंधक सुधीर दलाल और एसटीपीआई के निदेशक सुबोध सचान ने पात्र स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पीएनबी के मुताबिक एसटीपीआई बैंक के साथ इनक्यूबेटेड, ऑनबोर्डेड या ग्रेजुएटेड स्टार्टअप्स की एक चयनित सूची साझा करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह समझौता पीएनबी की स्टार्टअप केंद्रित योजनाओं और वित्तीय उत्पादों तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए स्टार्टअप्स और वित्तीय संस्थानों के बीच एक सेतु का काम करेगा।

टाटा स्टील पर अमेरिकी टैरिफ का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं, भारत में स्टील की मांग बढ़ रही : टीवी नरेंद्रन

पूर्वी सिंहभूम। बिष्टुपुर के सर दोराबजी टाटा पार्क में सर दोराबजी टाटा की जयंती पर श्रद्धांजलि समारोह में टाटा स्टील के एमडी और सीईओ टीवी नरेंद्रन ने कहा कि अमेरिका के 50 प्रतिशत आयात शुल्क का टाटा स्टील की भारतीय इकाइयों पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा। नरेंद्रन ने कहा कि टाटा स्टील भारत या जमशेदपुर से अमेरिका में स्टील का निर्यात नहीं करती, बल्कि यूरोप स्थित प्लांट से अमेरिकी बाजार में निर्यात होता है, जहां कुछ हद तक असर संभव है। नरेंद्रन ने यह भी बताया कि भारत में स्टील की घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है और सरकार द्वारा किए जा रहे आर्थिक सुधारों–जैसे जीएसटी में बदलाव और नीतिगत सुधारों–से भारतीय अर्थव्यवस्था और भी मजबूत हो रही है। हालांकि उन्होंने माना कि अमेरिकी टैरिफ का असर टेक्सटाइल, ज्वेलरी और जेम्स इंडस्ट्री पर पड़ सकता है, लेकिन इससे निपटने के लिए भारत सरकार निरंतर बैठकें कर रही है और उचित समाधान खोजे जा रहे हैं। इस अवसर पर टाटा स्टील के एमडी ने कहा कि कंपनी पिछले 119 वर्षों से राष्ट्र की सेवा कर रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने बताया कि टाटा स्टील हाइड्रोजन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास कर रही है ताकि पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन को बढ़ाया जा सके।

गेहूं-चावल सस्ता, खाद्य तेलों-दालों में घटबढ़, चीनी मजबूत

नई दिल्ली। घरेलू थोक जिंस बाजारों में चावल और गेहूं के औसत भाव बढ़ गये। चीनी की कीमतों में भी तेजी रही जबकि दालों और खाद्य तेलों की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया। विदेशों में मलेशिया के बुरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में नवंबर का पाम ऑयल वायदा 19 रिंगिट चढ़कर 4,489 रिंगिट प्रति टन बोला गया। वहीं, अमेरिकी सोया तेल वायदा 0.02 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 53.47 डॉलर के भाव बोला गया। घरेलू थोक जिंस बाजारों में चावल की औसत कीमत 75 रुपये घटकर 3,764.08 रुपये प्रति क्विंटल रह गयी। गेहूं 33 रुपये प्रति क्विंटल की नरमी के साथ 2,804.78 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। आटे की कीमत 22 रुपये टूटकर 3,271.26 रुपये प्रति क्विंटल रह गयी। सरसों तेल औसतन 85 रुपये प्रति क्विंटल महंगा हो गया। सूरजमुखी तेल 26 रुपये और मूंगफली तेल 83 रुपये चढ़ गया। वनस्पति 47 रुपये और पाम ऑयल 90 रुपये प्रति क्विंटल मजबूत हुआ। सोया तेल 41 रुपये प्रति क्विंटल टूट गया। दाल-दलहनों में तुअर दाल की औसत कीमत 35 रुपये प्रति क्विंटल टूट गयी। चना दाल 26 रुपये और उड़द दाल 34 रुपये प्रति क्विंटल उतर गयी। मूंग दाल में छह रुपये की गिरावट रही। मसूर दाल की कीमत छह रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गयी।

पहली छमाही में घरों की सुस्त बिक्री के बाद डेवलपर्स को त्योहारी मौसम से उम्मीद

नई दिल्ली। इस साल पहली छमाही में घरों की बिक्री में सुस्ती के बाद निवेशक त्योहारी सीजन में मांग आने की उम्मीद कर रहे हैं। हाउसिंग डॉट कॉम की जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि गणेश उत्सव से शुरू होकर नवरात्रि और दिवाली तक हर साल देश में सबसे अधिक लोग घर खरीदते हैं। यह त्योहारी मौसम वार्षिक बिक्री में लगभग एक-तिहाई योगदान देता है। रियल एस्टेट के बारे में डिजिटल जानकारी देने वाली कंपनी आरईए इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीन शर्मा ने कहा कि साल 2025 की पहली छमाही अपेक्षाकृत संतुलित रही है। त्योहारी मौसम में नये उत्साह के साथ डेवलपर आकर्षक पेशकश के साथ बड़े प्रोजेक्ट पेश करने की तैयारी में हैं। उसने उम्मीद जतायी कि मध्यम और प्रीमियम सेगमेंट में स्थिर मांग, उपभोक्ता विश्वास में सुधार, और लाइफस्टाइल आधारित हाउसिंग पर बढ़ते फोकस के कारण चौथी तिमाही मांग में सुधार होगा। हाउसिंग डॉट कॉम ने बताया कि पिछले पाँच वर्षों में (2020-24) सितंबर से दिसंबर तक के चार महीने लगातार हाउसिंग बिक्री के लिए सबसे मजबूत साबित हुये हैं।

सीएटीसीए ने छत्तीसगढ़ की कंपनियों के साथ बी2बी साझेदारी में रुचि दिखाई : मुख्यमंत्री

एजेंसी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय अपने दक्षिण कोरिया प्रवास के दौरान सियोल में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर एसोसिएशन (सीएटीसीए) के चेयरमैन ली जे जेंग एवं वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। सीएटीसीएएक सशक्त औद्योगिक नेटवर्क है, जिसमें आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फार्मा और टेक्सटाइल क्षेत्र की 60 से अधिक प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सीएटीसीए प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार निवेशकों के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ली जे जेंग और उनके साथ आए वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया कि वे अपने आगामी भारत दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ अवश्य आएं और राज्य में उपलब्ध निवेश व सहयोग की संभावनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन करें। सीएटीसीए ने छत्तीसगढ़ की कंपनियों के साथ बी2बी साझेदारी में

रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और एम्स जैसे राष्ट्रीय संस्थान मौजूद हैं, जो विश्वस्तरीय प्रतिभा उपलब्ध कराते हैं। राज्य का 'प्लग एंड प्ले' इंफ्रास्ट्रक्चर और सशक्त लॉजिस्टिक्स नेटवर्क छत्तीसगढ़ को सीएटीसीए के अनुसंधान एवं विकास केंद्रों और भारत में उनके विस्तार का स्वाभाविक हब बनाता है। विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ तेजी से विकसित हो रहा है और यहां उद्योग-अनुकूल नीतियां, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, कुशल मानव संसाधन तथा मजबूत बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फार्मा और टेक्सटाइल जैसे उभरते क्षेत्रों में सीएटीसीए कंपनियां यहां आकर निवेश करें और साझेदारी के नए आयाम स्थापित करें। इससे प्रदेश के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और स्थानीय उद्योगों को भी नई ताकत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अपने दक्षिण कोरिया प्रवास के दौरान सियोल में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में भाग लिया, जिसका आयोजन इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स इन कोरिया (आईसीसीके) के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए असीम संभावनाओं की धरती है। उन्होंने उल्लेख किया कि दक्षिण कोरिया भारत के शीर्ष तीन इस्पात निर्यात गंतव्यों में शामिल है ।

सीआरआईटी केंद्र भारत के व्यापार हितों को आगे बढ़ाने में निभा रहे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां : वाणिज्य सचिव

एजेंसी

नई दिल्ली। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केंद्र (सीआरआईटी) केंद्र भारत के व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। वाणिज्य सचिव ने राजधानी नई दिल्ली के तीन मूर्ति भवन स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय में आयोजित व्यापार एवं निवेश विधि केंद्र (सीटीआईएल) के 8वें वर्षगांठ समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस कार्यक्रम के बतौर मुख्यातिथि सुनील बर्थवाल ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि इन केंद्रों द्वारा किया जा रहा कार्य भारत के राष्ट्रीय हितों से गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि व्यापार वार्ताओं की गोपनीयता बनाए रखने के लिए इनकी स्थापना अत्यंत महत्वपूर्ण है, साथ ही यह मजबूत आंतरिक क्षमता के विकास में भी योगदान देगा। वाणिज्य मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और इस कार्यक्रम के मुख्यातिथि न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने अपने संबोधन में राज्य की क्षमता विकास में वकीलों और थिंक टैंकों की भूमिका पर ज़ोर दिया, जिसका शासन कला में रणनीतिक महत्व है। चंद्रचूड़ ने कहा कि सीटीआईएल की भूमिका व्यापार और निवेश कानून के क्षेत्र में आवश्यक विशेषज्ञता और कौशल लाकर सरकार की क्षमता को बढ़ाने में है। उन्होंने बताया कि कैसे क्षमता निर्माण की पहलों ने व्यापार वार्ताओं और समझौतों में परिणाम देने शुरू कर दिए हैं। चंद्रचूड़ ने ट्रेडलैब जैसे अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रमों में सीटीआईएल के प्रयासों का उल्लेख किया और अन्य विधि विद्यालयों में इसके विस्तार की वकालत की।

कैबिनेट ने 12,328 करोड़ रुपये की लागत से चार रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय की चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। इनकी कुल अनुमानित लागत 12,328 करोड़ रुपये है। इनमें एक नई रेल लाइन परियोजना गुजरात के कच्छ क्षेत्र में तथा तीन मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाएं कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और असम में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। मंजूर की गई परियोजनाओं में देशलपार-हाजीपीर-लूना एवं वायोर-लाखपत नई रेल लाइन, सिकंदराबाद (सनथनगर)-वाडी तीसरी एवं चौथी लाइन, भागलपुर-जमालपुर तीसरी लाइन तथा फुरकेटिंग-न्यू तिनसुकिया दोहरीकरण शामिल हैं। गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और असम राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली ये चार परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 565 किलोमीटर बढ़ा देंगी। सरकार के अनुसार, इन परियोजनाओं का उद्देश्य यात्रियों और माल दोनों का निर्बाध और तेज़ परिवहन सुनिश्चित करना है। ये पहल कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी और यात्रा सुविधा में सुधार के साथ-साथ रसद लागत को कम करेंगी और तेल आयात पर निर्भरता कम करेंगी। इसके अतिरिक्त, ये परियोजनाएं सीओ2 उत्सर्जन को कम करने में योगदान देंगी, जिससे टिकाऊ और कुशल रेल संचालन को बढ़ावा मिलेगा। परियोजनाओं से निर्माण अवधि के दौरान करीब 251 लाख मानव-दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है।प्रस्तावित नई रेल लाइन कच्छ क्षेत्र के सुदूर इलाकों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। यह गुजरात के मौजूदा रेलवे नेटवर्क में 145 रूट किमी और 164 ट्रैक किमी जोड़ेगी। इस पर 2526 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है और इसे तीन वर्षों में पूरा किया जाएगा। गुजरात राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा, यह नई रेल लाइन नमक, सीमेंट, कोयला, क्लिंकर और बेंटोनाइट के परिवहन में भी मदद करेगी। इस परियोजना का सामरिक महत्व यह है कि यह कच्छ के रण को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। हड़प्पा स्थल धोलावीरा, कोटेश्वर मंदिर, नारायण सरोवर और लखपत किला भी रेल नेटवर्क के अंतर्गत आएंगे क्योंकि 13 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे जिससे 866 गांवों और लगभग 16 लाख आबादी को लाभ होगा। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, स्वीकृत तीन मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं से लगभग 3,108 गांवों और लगभग 47.34 लाख की आबादी और एक आकांक्षी जिले (कलबुर्गी) तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इससे कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और असम राज्यों को लाभ होगा। इसमें कर्नाटक और तेलंगाना में फैली 173 किमी लंबी सिकंदराबाद (सनथनगर)- वाडी तीसरी एवं चौथी लाइन पर 5012 करोड़ रुपये खर्च होंगे और यह पांच साल में पूरी होगी।

पीएम स्वनिधि योजना की ऋण अवधि के पुनर्गठन और विस्तार को मंजूरी

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना' की ऋण अवधि के पुनर्गठन और विस्तार को मंजूरी दी है। ऋण अवधि अब पिछले वर्ष 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को आज मंजूरी दी। इस योजना का कुल परिव्यय 7,332 करोड़ रुपये है। पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 50 लाख नए लाभार्थियों सहित 1.15 करोड़ लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाना है। एक सरकारी बयान के अनुसार पुनर्गठित योजना की प्रमुख विशेषताओं में पहली और दूसरी किस्त में बढ़ी हुई ऋण राशि, दूसरा ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों के लिए यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड का प्रावधान और खुदरा एवं थोक लेनदेन के लिए डिजिटल कैशबैक प्रोत्साहन शामिल हैं। इस योजना का दायरा वैधानिक शहरों से आगे बढ़कर जनगणना शहरों, अर्ध-शहरी क्षेत्रों आदि तक चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है। उन्नत ऋण संरचना में पहली किस्त के ऋण को बढ़ाकर 15 हजार रुपये (10 हजार रुपये से) और दूसरी किस्त के ऋण को बढ़ाकर 25 हजार रुपये (20 हजार रुपये से) कर दिया गया है, जबकि तीसरी किस्त 50 हजार रुपये पर अपरिवर्तित रहेगी यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड की शुरुआत से रेहड़ी-पटरी वालों को किसी भी आकस्मिक व्यावसायिक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तुरंत ऋण उपलब्ध होगा। इसके अलावा, डिजिटल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए, रेहड़ी-पटरी वाले खुदरा और थोक लेनदेन पर 16 सौ रुपये तक के कैशबैक प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना उद्यमिता, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल कौशल और विपणन पर ध्यान केंद्रित करते हुए रेहड़ी-पटरी वालों की क्षमता निर्माण पर भी केंद्रित है। एफएसएसएआई के साथ साझेदारी में रेहड़ी-पटरी वालों के लिए मानक स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान अभूतपूर्व कठिनाइयों का सामना करने वाले रेहड़ी-पटरी वालों की सहायता के लिए 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की थी। हालांकि, इस योजना की शुरुआत से ही यह रेहड़ी-पटरी वालों के लिए वित्तीय सहायता से कहीं बढ़कर साबित हुई है और इसने उन्हें अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के लिए एक पहचान और औपचारिक मान्यता प्रदान की है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने पहले ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। 30 जुलाई तक 68 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों को 13,797 करोड़ रुपये के 96 लाख से अधिक ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

भारत में फरवरी 2025 तक 56.75 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए : केंद्र

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत में तेजी के इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाया जा रहा है और फरवरी 2025 तक 56.75 लाख ईवी पंजीकृत हुए हैं। यह जानकारी सरकारी डेटा में दी गई। डेटा के अनुसार, वित्त वर्ष 25 में देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री 11.49 लाख यूनिट्स रही थी, जो कि पिछले वित्त वर्ष के आंकड़े 9.48 लाख यूनिट्स से 21 प्रतिशत अधिक थी। यह आंकड़े बताते हैं कि लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सरकार ने भी 2030 तक कुल वाहनों की बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। सरकार ईवी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसमें हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेज अपनाना और निर्माण (फेम-2), पीएम ई-ड्राइव, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम,

पीएम ई-बस सेवा शामिल हैं। फेम-2 की सफलता को देखते हुए सरकार ने फेम-3 स्कीम को शुरू किया है, जिसके तहत 16,29,600 ईवी वाहनों को सपोर्ट किया जा रहा है, जिसमें दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और बस शामिल हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए, भारी उद्योग मंत्रालय ने मार्च 2023 में तीन तेल कंपनियों - इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन - को पूरे भारत में अपने ईंधन आउटलेट पर 7,432 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 800 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। मार्च 2024 में, 980 चार्जिंग स्टेशनों को अपग्रेड करने के लिए अतिरिक्त 73.50 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। 9,332 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पीसीएस की स्थापना के लिए कुल 912.50 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके तहत 30 जून, 2025 तक 8,885 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पीसीएस स्थापित किए जा चुके हैं, जो देश के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

सरकार ने आकाश त्रिपाठी को सेकी का प्रबंध निदेशक किया नियुक्त

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आकाश त्रिपाठी को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (सेकी) का प्रबंध निदेशक (एमडी) नियुक्त किया है।

सेकी ने जारी एक बयान में कहा कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने 1998 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी त्रिपाठी को भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव के पद और वेतन पर उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। बयान में कहा गया है, आईएएस आकाश त्रिपाठी को एमडी नियुक्त किया गया है, जबकि संतोष सारंगी चेयरमैन बने रहेंगे। इसके साथ ही सेकी का नेतृत्व ढांचा अब औपचारिक हो गया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव आईएएस संतोष सारंगी अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। संतोष सारंगी ने जारी बयान में कहा, त्रिपाठी की नियुक्ति से बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन, बेहतर संस्थागत समन्वय और हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण और हरित

ऊर्जा परियोजनाओं जैसी उभरती प्राथमिकताओं के क्रियान्वयन के लिए समर्पित नेतृत्व मिलेगा। सेकी ने कहा कि हमें नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (सेकी) के नए प्रबंध निदेशक के रूप में 1998 बैच के एमपी कैडर के आईएएस अधिकारी आकाश त्रिपाठी का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है।

योगी सरकार में देश के दिग्गज निवेशकों को भाया गोरखपुर

● **अडानी समूह और कोका कोला के प्रमुख बॉटलर ने भी उद्योग लगाने को ली जमीन**

एजेंसी

गोरखपुर। दशकों तक जिस गोरखपुर में स्थानीय पूंजीपति भी औद्योगिक निवेश करने से घबराते थे, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकार की प्रोत्साहनपरक नीतियों, कारोबारी सुगमता और शानदार कनेक्टिविटी से अब वहां नामी कंपनियों के आने की होड़ सी दिखती है। निवेशकों की डिमांड के अनुरूप गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) ने न केवल लैंड बैंक समृद्ध किया है बल्कि साल दर साल औद्योगिक भूखंडों का आवंटन भी तेज हुआ है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में तो गीडा ने अब तक 54 नई यूनिट्स के लिए रिकार्ड 182 एकड़ भूमि का आवंटन किया है। इससे 5800 करोड़ रुपये के नए पूंजी निवेश के साथ 8500 लोगों के लिए रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

योगी सरकार में देश के दिग्गज निवेशकों को भाया गोरखपुर:लंबे दौर तक पहचान को जूझता रहा गोरखपुर अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी के मामले में मजबूत होकर औद्योगिक नक्शे पर भी चमक गया है। जिस जिले से उद्यमियों ने मुंह फेर लिया था, वहां 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से औद्योगिक प्रगति का ऐसा माहौल बनना शुरू हुआ कि देश की बड़ी-बड़ी कंपनियां, यहां तक कि मल्टीनेशनल भी इंडस्ट्री लगा रही हैं।

औद्योगिक प्रगति के नए कालखंड में सिर्फ गत पांच साल की बात करें तो इस दौरान गीडा को 9445 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले और इसके जरिये 22922 रोजगार सृजन संभव हुआ। इसमें मल्टीनेशनल ब्रांड पेप्सिको, केयान डिस्टिलरी, ज्ञान डेयरी, टेक्नोप्लास्ट और केंद्रीय भंडारण निगम, कपिला कृषि उद्योग, एपीएल अपोलो ट्यूब्स जैसे बड़े नाम शामिल हैं। गोरखपुर में अडानी समूह ने अंबुजा ब्रांड सीमेंट फैक्ट्री की नई यूनिट और कोका कोला के प्रमुख बॉटलर अमृत बॉटलर्स ने भी यूनिट लगाने को जमीन ले ली है। यही नहीं, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड और श्री सीमेंट्स ने भी निवेश की उत्सुकता दिखाते हुए गीडा से औद्योगिक जमीन मांगी है। श्री सीमेंट्स की टीम पहले ही जमीन देखने के लिए दौरा कर चुकी है जबकि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के प्रतिनिधि विजिट पर आए थे। अपने पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्र के साथ गीडा ने गोरखपुर के दक्षिणांचल में धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप को भी औद्योगिक हब के रूप में विकसित करना शुरू कर दिया है। गत दिनों यहां दो बड़े औद्योगिक निवेश के लिए भूमि का आवंटन किया जा चुका है। गीडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुज मलिक का कहना है कि मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में गोरखपुर में निवेश और औद्योगिक विकास का शानदार इको सिस्टम तैयार हुआ है। गीडा द्वारा निवेशकों की मांग और पसंद के अनुरूप जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। इसका नतीजा है कि यहां औद्योगिक निवेश लगातार बढ़ रहा है।

जीएसटी काउंसिल 31 अक्टूबर तक सेस कर सकती है खत्म

एजेंसी

नई दिल्ली । वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बैठक 3 सितंबर को होने जा रही है। इस बैठक में 31 अक्टूबर तक क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त करने पर चर्चा की जा सकती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाला था। हालांकि, उपकर संग्रह को पहले ही समाप्त करने के लिए चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान राज्यों को राजस्व की कमी की भरपाई के लिए, लिए गए ऋण पूरी तरह से चुकाने के करीब पहुंच रहे हैं।

यह पुनर्भुगतान 18 अक्टूबर के आसपास पूरा होने की उम्मीद है, लेकिन सरकार सुचारू संचालन के लिए इसे अक्टूबर के अंत तक बढ़ा सकती है। सरकारी सूत्रों के हवाले से रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उपकर संग्रह से लगभग 2,000-3,000 करोड़ रुपए का अधिशेष प्राप्त हो सकता है, जिसे केंद्र और राज्यों के बीच समान रूप से साझा किया

जाएगा। कानून में क्षतिपूर्ति के लिए उपकर को केवल पांच वर्षों के लिए अनिवार्य किया गया था, क्योंकि राज्यों को चिंता थी कि 2017 में जीएसटी लागू होने पर उन्हें कर राजस्व का नुकसान होगा। इसलिए राज्य के राजस्व में कमी की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति उपकर लगाया गया था।केंद्र ने राज्यों की ओर से 2.69 लाख करोड़ रुपए उधार लिए और वित्तीय प्रबंधन में सहायता के लिए उन्हें ऋण के रूप में प्रदान किए। हालांकि, महामारी के दौरान लिए गए ऋणों के भुगतान हेतु, जब राजस्व में तेज गिरावट आई थी, इस उपकर को जून 2022 से मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया था। वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अनुसार, ऋणों का भुगतान पूरा होने के बाद उपकर संग्रह बंद हो जाएगा। वित्त मंत्रालय ने सभी वस्तुओं पर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो जीएसटी दरों के लिए जीएसटी परिषद को अपना प्रस्ताव भेजा है, जो मौजूदा चार स्लैब संरचना का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार, गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को कम करने के उद्देश्य से एक नियोजित जीएसटी सुधार के माध्यम से नागरिकों को इस दिवाली दोहरा बोनस मिलेगा।

अडानी समूह जयप्रकाश एसोसिएट्स का अधिग्रहण करेगा, सीसीआई की मंजूरी

नई दिल्ली। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने अडानी समूह की संस्थाओं द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के अधिग्रहण की योजना को मंजूरी दे दी है। आयोग का विस्तृत आदेश बाद में आएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के मुताबिक योजना के तहत अडाणी इंटरप्राइजेज लिमिटेड और अडाणी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड या समूह की अन्य कंपनियों द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड की शत-प्रतिशत अधिग्रहण किया जाएगा। जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड वर्तमान में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, इलाहाबाद पीठ के निर्देशों के अनुसार दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है।

अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड अडानी समूह की कंपनियों के पोर्टफोलियो की प्रमुख कंपनी है। अडाणी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, अडाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह अडाणी समूह के सभी रियल्टी व्यवसायों की होल्डिंग कंपनी है। अडाणी समूह का कारोबार ऊर्जा, संसाधन, लॉजिस्टिक्स, सामग्री और कृषि जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है। जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड एक विविध अवसंरचना समूह है। इसका व्यवसाय इंजीनियरिंग एवं निर्माण, सीमेंट, बिजली, रियल एस्टेट, उर्वरक, आतिथ्य, खेल आदि क्षेत्रों में है।

भारत की जैव-अर्थव्यवस्था 2030 तक 300 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी: डॉ. जितेन्द्र सिंह

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की जैव-अर्थव्यवस्था 2014 में मात्र 10 अरब डॉलर थी, जो आज बढ़कर 165.7 अरब डॉलर हो गई। 2030 तक जैव अर्थव्यवस्था 300 अरब डॉलर के लक्ष्य हासिल कर लेगी। बायो ई 3 नीति के एक साल पूरे होने के मौके पर नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने पिछले एक साल में बायो ई 3 नीति के तहत तेजी से प्रगति की है और कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जो देश की जैव-अर्थव्यवस्था को आकार दे रही हैं। इस मौके पर डॉ. जितेन्द्र सिंह ने युवाओं के लिए बायो ई 3 चुनौती और देश के पहले राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क का शुभारंभ किया। उन्होंने जैव-प्रौद्योगिकी को भारत की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोज़गार का वाहक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने

अपने हितधारकों के साथ मिलकर कम समय में नए संस्थान स्थापित किए हैं, संयुक्त अनुसंधान पहल शुरू की हैं और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां स्थापित की हैं। देश भर में जैव-कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रों, जैव-विनिर्माण केंद्रों और जैव-फाउंड्री की स्थापना, और कोशिका एवं जीन थेरेपी, जलवायु-अनुकूल कृषि, कार्बन कैप्चर और कार्यात्मक खाद्य पदार्थों जैसे उन्नत क्षेत्रों को कवर करने वाले एक दर्जन से अधिक संयुक्त अनुसंधान कॉलों के शुभारंभ का उल्लेख किया। डीबीटी को इन श्रेणियों के अंतर्गत पहले ही 2,000 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।डॉ. जितेंद्र ने कहा कि इस वर्ष की शुरुआत में ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग (डीबीटी) समर्थित तीन प्रयोग किए गए थे। राज्य स्तर पर, डीबीटी ने केंद्र-राज्य साझेदारी की पहल की है, जिसमें असम के साथ एक बायो ई 3 प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन भी शामिल है। वैश्विक स्तर पर, 52 देशों में भारत के मिशनों ने बायो ई 3 नीति पर इनपुट साझा किए हैं, और डीबीटी और विदेश मंत्रालय अनुवर्ती कार्रवाई पर काम कर रहे हैं। इस मौके पर डीबीटी सचिव डॉ. राजेश गोखले ने कहा आज शुरू किए गए दो नई पहल के बारे में कहा कि विभाग स्कूली छात्रों (कक्षा 6-12), विश्वविद्यालय के छात्रों, शोधकर्ताओं, संकाय, स्टार्टअप और भारतीय नागरिकों को स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण और उद्योग में चुनौतियों का समाधान करने वाले सुरक्षित जैविक समाधान डिजाइन करने के लिए आमंत्रित करती है। अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाले हर महीने की पहली तारीख को इस चुनौती की घोषणा की जाएगी।

सनी देओल की 'बाप' में इस FLOP एक्ट्रेस

उर्वशी रौतेला

की एंट्री, बढ़ा न दे संजय दत्त की मुश्किलें!

अब सनी देओल की बारी है. एक्शन किंग ने कुछ वक्त पहले ही 'बॉर्डर 2' का काम खत्म किया है. अब उन्हें रणबीर कपूर की 'रामायण' के लिए भी काम करना है. उससे पहले उनके खाते में कई बड़ी फिल्में भी हैं. इसी बीच उनकी मच अवेटेड फिल्म Baap पर बड़ा अपडेट सामने आ गया है. यूं तो इस फिल्म का काफी वक्त पहले काम कंप्लीट हो चुका है. साथ ही विलेन बने एक्टर ने भी कहा था कि इस साल फिल्म रिलीज हो सकती है. अब एक और जानकारी सामने आई है. जो न ही सनी देओल, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ को लेकर है, न ही मिथुन चक्रवर्ती पर. बल्कि एक फ्लॉप एक्ट्रेस की फिल्म में एंट्री हुई है.हाल ही में एक न्यूज वेब साइट पर नई रिपोर्ट छपी. जिसके मुताबिक, सनी देओल की फिल्म 'बाप' में एक एक्ट्रेस की एंट्री हो गई है. एक गाने में वो परफॉर्म करती नजर आएंगी. हालांकि, वो सनी देओल और संजय दत्त की फिल्म के लिए किसी खतरें से कम नहीं हैं. जानिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है ?

सनी देओल की 'बाप' में कौन ?

दरअसल सनी देओल की फिल्म लंबे वक्त से अटकी हुई है. फिल्म पर कोई अपडेट सनी देओल या फिर मेकर्स की तरफ से शेयर नहीं किया गया. पर सोशल मीडिया के जरिए जानकारी सामने आती रहती है. लेकिन नई रिपोर्ट से पता लगा कि अहमद खान ने फिल्म में स्पेशल नंबर के लिए उर्वशी रौतेला को चुना है. यह पॉपुलर गाने अप्सरा आली का रीमेक होगा. कहा जा रहा है कि उर्वशी रौतेला फिल्म का शूट पहले ही कर चुकी हैं. 3 दिन में गाने का शूट भी कंप्लीट कर लिया गया है.

वो फिल्म में सनी देओल के अलावा संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और मिथुन चक्रवर्ती के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आने वाली हैं. कहा जा रहा है कि यह फिल्म हॉलीवुड की 'एक्सपेंडेबल्स' का बॉलीवुड रीमेक है. जिस गाने का फिल्म में रीमेक होगा, वो 'नटरंग' का 'अप्सरा आली' गाना है. यह एक मराठी सॉन्ग है. हाल ही में उर्वशी रौतेला को सनी देओल की फिल्म जाट में भी देखा गया था. जिसमें भी उनका 'सॉरी बोल' नाम का स्पेशल गाना था.

क्यों है सनी देओल के लिए खतरा ?

दरअसल सनी देओल और उर्वशी रौतेला एक ही फिल्म में साथ काम कर चुके हैं. फिल्म 'सिंह साब द ग्रेट' में उर्वशी उनकी पत्नी के रोल में थीं. हालांकि, फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही थी. अब 'जाट' में दिखी, तो फिल्म खास परफॉर्म नहीं कर पाई. देखना होगा कि बाप वाले अपडेट में कितनी सच्चाई है ?

एक साथ बप्पा का स्वागत करते दिखे गोविंदा-सुनीता, तलाक की खबरों पर तोड़ी चुप्पी

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं. कई बार अपने किसी स्टेमेंट को लेकर तो तभी अपनी संग तलाक की अफवाहों को लेकर. कुछ महीनों पहले इस बात की अफवाह ने जोर पकड़ा था, कि गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता के बीच कुछ भी ठीक नहीं है और दोनों तलाक ले रहे हैं. वहीं बीते दिनों ये बात भी सामने आई थी कि सुनीता ने गोविंदा पर गंभीर आरोप लगाए हैं, और तलाक के लिए अर्जी दे दी है. इस बात को लेकर गोविंदा के फैंस काफी चिंता में थे.इसी बीच आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर दोनों ने साथ में अपीरियंस दी. ना सिर्फ गोविंदा और सुनीता साथ दिखे बल्कि दोनों ने एक साथ मिलकर घर पर धूमधाम से बप्पा का स्वागत भी किया. इस मौके पर सुनीता और गोविंदा ने फैंस को गणेश चतुर्थी की बधाई दी और अपने तलाक को लेकर भी चुप्पी तोड़ी.

तलाक की खबरों पर क्या बोले गोविंदा-सुनीता ?

सोशल मीडिया पर गोविंदा और सुनीता का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में गोविंदा पत्नी सुनीता के साथ नजर आ रहे हैं और साथ ही वो मीडिया से बात करते भी दिखाई दे रहे हैं. मीडिया की तरफ से जब उनसे उनके तलाक को चल रही अफवाहों पर सवाल किया जाता है तो सुनीता अपने मस्ती भरे अंदाज में कहती हैं- तुम लोग कंट्रोवर्सी सुनने के आए हो, या फिर बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए. कोई कंट्रोवर्सी नहीं है. साथ ही गोविंदा भी इसी बीच जोर से बप्पा के नाम का उद्घोष करते नजर आते हैं.

1987 में हुई थी कपल की शादी

ये वीडियो देखने के बाद फैंस ने राहत की सांस ली है. आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सुनीता और गोविंदा के तलाक के रुमर्स सामने आए हों. इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है. हालांकि, हर बार ये अफवाह ही निकलती है. बात करें दोनों के रिश्ते की तो सुनीता और गोविंदा की शादी साल 1987 में हुई थी. दोनों के दो बच्चे हैं.

'मां कमाती थीं, पिता घर पर रहते थे...' इन हालातों में बीता सोहा अली खान का बचपन

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान ने हाल ही में अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताया कि क्रिकेटर होने के बावजूद उनके पिता घर में रहते थे, जबकि उनकी मां और दिग्गज एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर काम करती थीं और उनका घर चलाती थीं. शादी और बच्चों के बाद भी शर्मिला ने काम करना जारी रखा था.

बॉलीवुड अभिनेत्री सोहा अली खान ने अपनी मां और दिग्गज एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर की राह पर चलते हुए हिंदी सिनेमा में ही अपना करियर बनाया. हालांकि वो मां की तरह लोकप्रियता और सफलता हासिल नहीं कर पाईं. सोहा ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन टॉप एक्ट्रेस के रूप में पहचान बनाने में नाकाम रहीं. हाल ही में एक बातचीत में एक्ट्रेस ने अपने बचपन के दिनों को याद किया है और बताया कि उनकी मां कमाती थीं और उनके पिता घर पर रहते थे.

सोहा अली खान की मां शर्मिला टैगोर जहां एक्ट्रेस रहीं तो वहीं उनके दिवंगत पिता मंसूर अली खान पटौदी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके थे. वो भारत के लिए कई मैच खेले. हालांकि कई बार क्रिकेटर होने के बावजूद वो घर पर बैठे रहते थे. तब क्रिकेट में काफी कम कमाई हुआ करती थी. लेकिन, तब उनकी पत्नी शर्मिला ने शादी के बावजूद फिल्मों से ब्रेक नहीं लिया और काम करना जारी रखा.

'मां कमाती थीं, पिता घर पर रहते थे...'

आम तौर पर देखा जाता है कि शादी या बच्चे होने के बाद एक्ट्रेसेस फिल्मी दुनिया से दूरी बना लेती हैं या कुछ समय के लिए ब्रेक ले लेती हैं.

हालांकि शर्मिला टैगोर ने ऐसा नहीं किया था. सोहा ने बताया, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी तरह का कोई शक था. ये एक सामान्य बात थी और मेरा मानना था कि जब हम छोटे थे, तो हमारे पिता घर पर होते थे और मां कभी काम पर होती थीं तो कभी हमारे साथ होती थीं. लेकिन, घर चलाने वाली मेरी मां ही थीं.

घर रहकर बच्चों को सभालते थे मंसूर

चाहे क्रिकेटर होने के बावजूद मंसूर को कई बार घर में रहना पड़ा हो, लेकिन वो इस दौरान शर्मिला की गैर मौजूदगी में अपने बच्चों को संभालते थे और उनकी अच्छे से देखभाल करते थे. शर्मिला ने एक बातचीत में बताया था कि जब उनके बेटे सैफ अली खान का जन्म हुआ था तो वो शुरू के 6 साल तक बेटे की जिंदगी से गायब रहीं.

यानी वो उन्हें पर्याप्त समय नहीं दे पाईं. एक्ट्रेस के मुताबिक वो दो-दो शिफ्ट में काम करती थीं. लेकिन उनके पति उस वक्त घर में रहकर घर और परिवार संभालते थे.

'लाहौर 1947' छोड़िए

प्रीति जिंटा

के हाथ लगे 2 बड़े प्रोजेक्ट, सनी देओल से बड़ा तूफान लाएंगी!

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा की वापसी का उनके फैन्स को बेसब्री से इंतजार है. लंबे वक्त से वो किसी फिल्म में नहीं दिखी हैं. हालांकि, भारत भी तब ही आती हैं, जब आईपीएल की शुरुआत होती है. जिसके बाद अपने परिवार के पास वापस विदेश लौट जाती हैं. यूं तो पहले ही कंफर्म हो चुका है कि वो सनी देओल की 'लाहौर 1947' से वापसी को तैयार है. हालांकि, फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं मिल रहा है कि कब तक काम कंप्लीट किया जाएगा. हालांकि, इस फिल्म के अलावा उनक खाते में दो और प्रोजेक्ट है. जानिएदरअसल आखिरी बार प्रीति जिंटा को 2018 में आई 'भैयाजी सुपरहिट' में देखा गया था. अब वो बॉलीवुड और हॉलीवुड के हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स से वापसी करने की तैयारी है. जिसमें एक संजय लीला भंसाली के साथ भी है. आइए जानते हैं उनके प्रोजेक्ट के बारे में.

बड़ी वापसी को तैयार प्रीति जिंटा!

यह तो कंफर्म है कि प्रीति जिंटा को सनी देओल के साथ देखा जाएगा. उनकी लाहौर 1947 के लिए फैन्स भी काफी एक्साइटेड हैं. वहीं इस फिल्म के प्रोड्यूसर आमिर खान हैं. जिनका पिक्चर में कैमियो होने की बात भी कही जा रही है. पर अब भी काम अटका हुआ है, जिसे लेकर रिलीज डेट पर कोई अपडेट नहीं मिला है. एक वेब साइट की खबर के मुताबिक, फिल्म को नवंबर 2025 या 2026 की शुरुआत में रिलीज करने की प्लानिंग चल रही है. हालांकि, बड़ा अपडेट भंसाली की 'हीरामंडी 2' पर मिला है.इसी रिपोर्ट से पता लगा कि 'हीरामंडी 2' में प्रीति जिंटा भी नजर आ सकती हैं. कहा जा रहा है कि पार्ट 2 के अहम रोल के लिए उनके नाम पर चर्चा चल रही है. दरअसल पहले पार्ट के बाद सोशल मीडिया पर कहा गया था कि प्रीति जिंटा को एक रोल के लिए चुना जा सकता है. भंसाली उन्हें एक अहम रोल के लिए लॉक कर सकते हैं. वहीं YRF भी एक फिल्म को लेकर उनसे बात कर रहे हैं. यह रोमांटिक क्राइम ड्रामा इस साल के एंड तक शुरू हो सकती है.

हॉलीवुड प्रोजेक्ट भी मिल गया ?

ऐसी भी चर्चा है कि काफी बातचीत के बाद प्रीति जिंटा ने हॉलीवुड प्रोडक्शन के लिए हामी भर दी है. यह मिंडी कलिंग और लीना डनहम की एक नई सीरीज है. लॉस एंजिल्स और न्यूयॉर्क में कई मुलाकात के बाद यह फाइनल किया गया. अब उनके खाते में कई बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए हैं. हालांकि, किस भारतीय फिल्म में जल्द दिखाई देंगी, इसे लेकर अब भी कन्फ्यूजन बना हुआ है.

हमारी समृद्ध परंपरा व आधुनिक तकनीकों का संगम है अवधी पाककला : कुलपति

कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में कल्याणपुर स्थित छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय परिसर में स्थित स्कूल आफ होटल मैनेजमेंट में अवधी पाककला एवं आर्ट ऑफ आइसिंग एंड बेकिंग विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम के द्वितीय दिवस पर लखनऊ से आगंतुक व अवधी पाककला पर विशेषज्ञ सेलिब्रिटी शेफ अलका सिंह तोमर, शेफ अनीता पासी व शेफ प्रतिमा चौधरी ने बेकरी व्यंजन प्लम केक, मल्टीग्रेन ब्रेड, ब्लैक फॉरेस्ट केक, पिज्जा

कुकीज आदि को स्कूल आफ होटल मैनेजमेंट के सभी छात्र-छात्राओं को बनाना सिखाया एवं इसके साथ सभी छात्र-छात्राओं के साथ आइसिंग एंड बेकिंग विषय के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करके उनका ज्ञानवर्धन किया। यह जानकारी बुधवार को सीएसजेएम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने दी।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने कहा कि होटल मैनेजमेंट के विद्यार्थियों द्वारा अवधी पाककला एवं आर्ट ऑफ आइसिंग एंड बेकिंग विषय पर कार्यशाला अत्यंत सराहनीय पहल है। यह आयोजन हमारी समृद्ध पाक परंपराओं और आधुनिक तकनीकों का संगम प्रस्तुत करता है। मैं सभी छात्रों और संकाय सदस्यों को इस सफल आयोजन के लिए हृदय से बधाई देता हूँ।

सेलिब्रिटी शेफ अलका सिंह तोमर ने विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई अच्छी हॉस्पिटैलिटी २एवं छात्र-छात्राओं के कार्यक्रम के प्रति सकारात्मक प्रदर्शन की बहुत तारीफ की एवं भविष्य में पुनः विभाग में मोटे अनाज पर एक कार्यशाला करने का वादा भी किया।

कार्यशाला के द्वितीय दिवस पर स्कूल आफ होटल मैनेजमेंट के डायरेक्टर सौरभ त्रिपाठी, असिस्टेंट डायरेक्टर शेफ सिद्धार्थ सिंह के साथ विभाग के अन्य सहायक आचार्य शिवांशु सचान, अरविंद चौहान, ऐश्वर्या आर्य, अंकित कुमार, डा रोबिन वर्मा एवं विभाग के प्रोफेसर ऑफ प्रेक्टिस अमित पाठक आदि उपस्थित रहे।

दुष्कर्म से पैदा अनचाहे गर्भ को गिराने की अनुमति

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म से उपजे अनचाहे गर्भ को गिराने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने यह आदेश डाक्टरों की टीम की जांच रिपोर्ट पर दिया है। कहा है कि नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति अर्जी पर निर्णय में देरी से पीड़िता के जीवन को खतरा होता है।

यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता तथा न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने दिया। बागपत के थाना सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र निवासी 17 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता की मां ने याचिका दायर कर अनचाहे गर्भ को समाप्त करने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने 22 अगस्त 2025 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागपत को एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया था। मेडिकल बोर्ड ने 23 अगस्त 2025 को पीड़िता की जांच की और अपनी रिपोर्ट में कहा कि भ्रूण की आयु 21 सप्ताह है ऐसे में अगर गर्भावस्था जारी रहती है तो यह पीड़िता के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। पीड़िता और उसके माता-पिता दोनों ने गर्भपात की प्रक्रिया के लिए सहमति दी है और पीड़िता पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है।

कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट और पीड़िता की सहमति के आधार पर गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दे दी है। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागपत और मेरठ को निर्देश दिया गया है कि वे लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, मेरठ के डॉक्टरों की एक टीम का गठन करें और तीन दिनों के भीतर गर्भपात की प्रक्रिया पूरी करें। साथ ही भ्रूण को फोरेंसिक जांच के लिए संरक्षित किया जाए। मेरठ के जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे पीड़िता और उसके परिवार के चिकित्सा और अन्य खर्चों का वहन करेंगे। कोर्ट ने अगली सुनवाई 2 सितम्बर को तय की है और रिपोर्ट मांगी है।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के पुनर्गठन पर योगी ने मोदी का किया आभार प्रकट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और ऋण अवधि को 31 मार्च 2030 तक बढ़ाने को लेकर प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया है।

उन्होंने ट्यूटर हैण्डल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अंत्योदय से राष्ट्रोदय' के संकल्प के सारथी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और ऋण अवधि को 31 मार्च 2030 तक बढ़ाने का निर्णय अभिनंदनीय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट कर लिखा कि कुल 7,332 करोड़ रुपए परिव्यय वाली इस पुनर्गठित योजना से 50 लाख नए लाभार्थियों सहित 1.15 करोड़ से अधिक रेहड़ी-पटरी व्यवसाय से जुड़े लाभार्थी आर्थिक-सामाजिक रूप से सशक्त होंगे। 'स्वनिधि से समृद्धि, स्वरोजगार से सम्मान' की भावना को साकार करते इस लोक-कल्याणकारी निर्णय हेतु प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार!

सीपीएल : चंडीगढ़ किंग्स और कैपिटल स्ट्राइकर्स का विजयी आगाज

चंडीगढ़: चंडीगढ़ प्रीमियर लीग (सीपीएल) 2025 का आगाज वीरवार को सेक्टर-16 क्रिकेट स्टेडियम में हुआ, जहां चंडीगढ़ किंग्स और कैपिटल स्ट्राइकर्स ने विजयी शुरूआत की। बारिश से प्रभावित मुकाबलों में ओवर घटाए गए। पहले मैच में किंग्स ने अल्टुइस्ट्रियंस को 18 रन से हराया। कप्तान शिवम भांबरी (38) और आरुष भंडारी ने ठोस शुरूआत दी, जिसके बाद निखिल ठाकुर ने 33 गेंदों पर नाबाद 61 रन (5 चौके, 4 छक्के) की आतिशी पारी खेली। रमन बिश्नोई ने 9 गेंदों पर 28 रन जोड़े और टीम ने 158/4 का स्कोर बनाया। जवाब में अल्टुइस्ट्रियंस 140/6 ही बना सके। निखिल ठाकुर मैन ऑफ द मैच चुने गए। दूसरे मुकाबले में कैपिटल स्ट्राइकर्स ने डॉ. मोरपेन डैजलर्स को 23 रन से हराया। स्ट्राइकर्स 119 रन पर आउट हुए, जिसमें अर्जुन आजाद ने 42 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए डैजलर्स 96/8 तक ही पहुंच पाए। जसकीरत सिंह मेहरा (4/20) की घातक गेंदबाजी ने मैच पलट दिया और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया।

हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास

फिरोजाबाद। न्यायालय ने बुधवार को हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना नसीरपुर के नगला नया हरिया निवासी श्यामवती पुत्री मुन्नालाल 11 अक्टूबर 2008 को खेत पर जा रही थी। रास्ते में वीनेश बैठा मिला। उसने गाली गलौज कर श्यामवती से मारपीट कर दी। श्यामवती ने घर पहुंचकर हाकिम सिंह को सारी बात बताई। उसकी बात सुन हाकिम सिंह हैरत में पड़ गया। वह तुरंत वहां पर पहुंचा। वहां पर विनेश अपने साथियों के साथ मिला। सभी हाथों में हथियार लिए थे। उन लोगों ने गाली गलोज कर हाकिम सिंह पर फायर कर दिए। गोली लगते ही वह गिर पड़ा। उसकी मौके पर मौत हो गई। उसके परिजनों ने वीनेश पुत्र सत्यप्रकाश, अरविंद पुत्र महीपाल, पप्पू उर्फ धर्मवीर पुत्र राम ब्रेश, महेश पुत्र किताब सिंह तथा गंभीर सिंह पुत्र बुद्ध सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

पुलिस ने मामले में हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा सत्र न्यायाधीश डॉ बब्बू सारंग की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी डीजीसी राजीव उपाध्याय ने की। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान गंभीर सिंह की मृत्यु हो गई। मुकदमे में कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने विनेश, अरविंद, धर्मवीर तथा महेश को दोषी माना। न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उन पर 54 - 54 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

बेटी के साथ पत्नी ने पति को पीट-पीट कर उतारा मौत के घाट

अमेठी। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां पर ना तो एक बेटी ने अपने बाप का लिहाज रखा और ना ही एक महिला ने अपने पति का साथ दिया। इस घटना में मां बेटी की पिटाई से पति की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस मां बेटी को हिरासत में लेकर पूछताछ और विधिक कार्यवाही शुरू कर दिया है।

बुधवार को गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चंदईपुर गांव निवासी राम अंजोर चौहान (55) का किसी बात को लेकर घर में विवाद हो गया। इस दौरान राम अंजोर चौहान की पत्नी ने अपनी बेटी अमिता के साथ मिलकर लाठी डंडों से हमला कर दिया । बताया जा रहा है की मां बेटी के इस हमले में राम अजोर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली प्रभारी सहित पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। इसके बाद जिले के अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।

गौरीगंज कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक इंस्पेक्टर श्याम नारायण पांडेय ने बताया कि गेहूं पिसवाने को लेकर घर में विवाद शुरू हुआ था । इसके बाद मारपीट हो गई जिसमें राम अंजोर की मौत हो गई है। मृतक की पत्नी और उसकी बेटी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मृतक के लाश को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

दो पहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह के चार सदस्य गिरफ्तार

प्रयागराज। उप्र के प्रयागराज जिले में स्थित सराय इनायत थाने की पुलिस टीम ने बुधवार को दो पहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए चार सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने उनके कब्जे से चोरी की तीन मोटरसाइकिल एवं एक मोबाइल फोन बरामद किया है। अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर पुष्कर वर्मा ने बताया कि गिरफ़्तार आरोपितों में सरायइनायत थाना क्षेत्र के कतवारूपुर गांव निवासी अमर सिंह उर्फ मोनू सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह , इसी थाना क्षेत्र के तेन्दुई गांव निवासी मनिंदर पाल पुत्र रामनिहोर पाल , कतवारूपुर गांव निवासी आदर्श सिंह पुत्र कौशल कुमार सिंह उर्फ पंकज सिंह , इसी थाना क्षेत्र के बक्सेपुर गांव निवासी अमर सिंह भारतीया पुत्र संटू भरतीया प्रयागराज है। उन्होंने बताया कि अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को मुखबिर की सूचना पर उक्त तीनों आरोपितों को गिरफतार किया और विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया।

बुजुर्ग व दिव्यांग जन हमारे समाज की अमूल्य धरोहर : सांसद

कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएगी। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत भाजपा पार्टी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करेगी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर बुजुर्गों एवं दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। इसी क्रम में बुधवार को किदवई नगर साईट नंबर वन चौराहे के निकट भाजपा दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह के मातादीन पेट्रोल पंप पर पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि सांसद रमेश अवस्थी उपस्थित रहे। यह जानकारी बुधवार को दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह ने दीं।

दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह ने बताया कि बतौर मुख्य अतिथि सांसद रमेश अवस्थी, क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल व विधायक महेश त्रिवेदी ने फीता काटकर पंजीकरण शिविर का शुभारंभ किया।साथ ही भाजपा दक्षिण जिलाध्यक्ष ने पुष्प गुच्छ भेंटकर अतिथियों का स्वागत किया।

उन्होंने बताया कि शिविर में मौजूद भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) की आठ सदस्यीय टीम द्वारा परीक्षण कर 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके 246 बुजुर्गों एवं दिव्यांगों का निः शुल्क पंजीकरण किया गया। जिन बुजुर्गों

के पास आय प्रमाण पत्र नहीं थे मौके पर मौजूद क्षेत्रीय पार्षदों द्वारा मौके पर ही तत्काल आय प्रमाण पत्र बनाए गए। इन सभी को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर निःशुल्क उपकरण वितरित किए जाएंगे।

क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कहा कि भाजपा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के लिए निःशुल्क उपकरण वितरण समारोह आयोजित करेगी।

सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि पंजीकरण शिविर का उद्देश्य बुजुर्गों एवं दिव्यांगों को आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराना है। बुजुर्ग और दिव्यांग जन हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उनके जीवन को सरल और गरिमापूर्ण बनाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार निरंतर कार्यरत है। इस पंजीकरण शिविर के माध्यम से हम उन्हें आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराकर उनकी दैनिक जीवनचर्या को सहज बनाने का प्रयास है।

भाजपा दक्षिण जिला मीडिया प्रभारी मनीष त्रिपाठी के मुताबिक गुरुवार को छावनी विधानसभा में श्याम नगर में पार्षद निर्देश सिंह चौहान के कार्यालय और रेलबाजार मैदान में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) द्वारा दिव्यांग उपकरण पंजीकरण शिविर लगाया जाएगा। यहां एलिम्को की टीम प्रातः साढ़े नौ बजे से सायं पांच बजे तक पंजीकरण करेगी।

60 वर्ष के बुजुर्गों के लिए केवल आधार कार्ड और दिव्यांगों के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र आवश्यक है।

प्रमुख रूप से रघुनंदन भदौरिया, गणेश शुक्ला, जसविंदर सिंह,मनीष त्रिपाठी, बिट्टू परिहार, विनीत दुबे,दीपांकर मिश्रा , दीपू पासवान,पार्षद डॉ अखिलेश बाजपेई, गिरीश बाजपेई,सुधीर यादव ,निक्कू तिवारी, सुनील कन्नौजिया, आदि मौजूद रहे।

भर्ती से पूर्व के मुकदमों को छिपाना महंगा पड़ा सिपाही को, एसएसपी ने किया बर्खास्त

मुरादाबाद। मुरादाबाद जनपद के थाना पाकबड़ा का सिपाही प्रभात पुंडीर को भर्ती से पूर्व के मुकदमों को छिपाना महंगा पड़ गया। शिकायत मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने सिपाही के क्रियाकलापों की जांच कराई। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर एसएसपी ने सिपाही को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया।

सहारनपुर जिले का रहने वाला पाकबड़ा थाने में तैनात था। सिपाही के खिलाफ एसएसपी को एक शिकायत मिली थी। आरोप था कि सिपाही ने अपने पूर्व के मुकदमों को छिपाते हुए नौकरी हासिल कर ली है। एसएसपी सतपाल अंतिल ने इस शिकायत की जांच क्षेत्राधिकारी हाईवे राजेश कुमार को करने के निर्देश दिए थे। सीओ हाईवे की प्रारम्भिक जांच से पता चला कि प्रभात पुंडीर के खिलाफ भर्ती होने से पहले ही सहारनपुर के बढ़गांव थाने में चार मुकदमे और देवबंद थाने में एक एनसीआर कायम है। नियमानुसार भर्ती का आवेदन करते समय प्रभात पुंडीर को इन मुकदमों की जानकारी देना आवश्यक था, लेकिन उसने इस तथ्य को भर्ती बोर्ड से छिपा लिया।

महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने के आरोप में तीन पर केस दर्ज

मुरादाबाद। महानगर के थाना मझोला क्षेत्र निवासी महिला ने थाना पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके गांव का रहने वाला एक युवक आए दिन आते-जाते उस पर अश्लील कमेंट करता है। सप्ताह भर पहले जब वह अपने घर में सो रही तो आरोपित युवक ने उससे दुष्कर्म की कोशिश की। महिला के शोर मचाने पर उसका भांजा आया तो आरोपित धक्का देकर भाग निकला। अगले दिन जब वह थाने शिकायत करने जा रही थी तो आरोपित ने अपनी पत्नी व अन्य एक युवक के साथ मिलकर उसके साथ गाली गलौज और मारपीट की। साथ ही घटना की शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

मझोला थाना क्षेत्र निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि उसके पति मजदूरी करते हैं। उसके गांव का रहने वाला विक्की आए दिन आते-जाते अश्लील कमेंट करता है। उसने पति से बात करने के लिए मोबाइल नंबर ले लिया। इसके बाद वह कॉल कर महिला को परेशान करने लगा। बातचीत के दौरान उसने पति को जहर देने का सुझाव दिया। महिला ने इस बात का विरोध किया तो वह उससे रंजिश रखने लगा। आरोपित के ममेरे भाई अमन ने कॉल कर धमकी दी कि उसके बातचीत का वीडियो वायरल कर देगा। महिला ने आरोप लगाया कि 20 अगस्त की रात नौ बजे जब महिला अपने घर में सो रही थी। इसी समय विक्की उसके घर में घुस गया। उसने महिला से छेड़छाड़ के बाद दुष्कर्म की कोशिश की। महिला के शोर मचाने पर छत पर सो रहा उसका भांजा बचाने के लिए आया तो आरोपी धक्का देकर मौके से भाग निकले। अगले दिन थाने जाते समय आरोपित विक्की, उसकी पत्नी रीनू ने रास्ते में रोककर गाली गलौज और मारपीट की।

थाना मझोला प्रभारी रवींद्र कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर पुलिस ने विक्की, उसकी पत्नी रीनू और ममेरे भाई अमन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया गया है।

एक राष्ट्र, एक चुनाव न केवल बाबा साहब के संविधान को मजबूत करेगा, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा भी करेगा : अनूप गुप्ता

कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में नगर निगम मुख्यालय में स्थित प्रमिला सभागार में भारतीय जनता पार्टी कानपुर महानगर उत्तर एवं दक्षिण जिलों की संयुक्त महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक का मुख्य विषय "एक राष्ट्र, एक चुनाव" था। बैठक में मुख्य वक्ता के तौर पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री,क्षेत्रीय प्रभारी अनूप गुप्ता उपस्थित हुए। यह जानकारी बुधवार को कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए दी। मुख्य वक्ता प्रदेश महामंत्री व क्षेत्रीय प्रभारी अनूप गुप्ता ने कहा कि भाजपा बाबा साहब डॉ.भीमराव अंबेडकर के संविधान को आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि 1952 में जब देश में प्रथम आम चुनाव हुए, तब लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। यह सिलसिला 1952, 1957, 1962 और 1967 तक समय पर चलता रहा। उन्होंने कहा कि 1967 के बाद कांग्रेस की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने

1972 में होने वाले आम चुनाव को समय से पहले 1971 में कराकर संविधान की मूल भावना की हत्या शुरू की। इसके बाद कांग्रेस ने राज्यों की सरकारों को अस्थिर करने और धनबल के सहारे सरकारें गिराने का खेल शुरू किया, जिससे लोकसभा और विधानसभा चुनावों का प्राकृतिक समय गड़बड़ा गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र, एक चुनाव न केवल बाबा साहब के संविधान को मजबूत करेगा, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा भी करेगा। इस व्यवस्था से देश को कई बड़े लाभ होंगे लगभग 7 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी। देश की विकास यात्रा और तेज गति से आगे बढ़ेगी।

Published, printed and owned by Rajesh.Chauhan, printed at B B Graphic printer Z--57 Okhla Industrial Area ph.2 New Delhi -110020 and published at BG 6 305 B Paschim Vihar New Delhi --110063 Editor Rajesh.Chauhan. E mail ID-rajeshchauhan4569@gmail.com, Contact No. - 9873104569, RNI No.- DLHIN/25/A2321